छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
<u>दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर</u>

क्रमांक 149 /एल-3-1/2012/ब-4/चार रायपुर, दिनांक 10/05/2012

प्रति,

प्रमुख सचिव/ सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन

वन / पंचायत एवं ग्रामीण विकास / वित्त /योजना, आर्थिक एवं सांख्यकीय / गृह/ जेल / लोक निर्माण / राजस्व एवं आपदा प्रबंधन / आवास एवं पर्यावरण / खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण /नगरीय प्रशासन एवं विकास / महिला एवं बाल विकास / सामान्य प्रशासन / स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण / संस्कृति विभाग मंत्रालय, रायपुर.

विषयः-तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान हेतु राज्य उच्च अधिकार समिति की वर्ष 2012-13 की प्रथम बैठक दिनांक 07 मई, 2012 का कार्यवृत्त ।

----0000----

विषयांतर्गत राज्य उच्च अधिकार समिति की वर्ष 2012-13 की प्रथम बैठक दिनांक 07 मई, 2012 का कार्यवृत्त आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

2. तेरहवें वित्त आयोग के संबंध में भारत सरकार के दिशा निर्देश, राशि की विमुक्ति एवं अन्य संबंधित जानकारी वित्त विभाग के वेबसाईट **http://cgfinance.nic.in** पर उपलब्ध है ।

संलग्न-उपरोक्तानुसार ।

10/05/2012

(डॉ.ए.के.सिंह)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक 150 /एल-3-1/2012/ब-4/चार रायपुर, दिनांक 10/05/2012

प्रतिलिपि-

1. संचालक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग, ब्लाक नं. -11, 5 वीं मंजिल, सी.जी.ओ.कांप्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
2. स्टाफ आफिसर, छ.ग. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, रायपुर .
3. प्रोग्रामर, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, रायपुर.

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,वित्त विभाग

Prog (FMIS) upload Act

तेरहवें वित्त आयोग अनुशंसा अनुदान हेतु दिनांक 07/05/2012 को आयोजित राज्य उच्च अधिकार अनुश्रवण समिति की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 07 मई, 2012 को राज्य उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति की प्रथम बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न हुई । बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है । बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

एजेण्डा कमांक-1. गत बैठक में लिये गये निर्णयों पर हुई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति-

प्रमुख सचिव वित्त द्वारा समिति की बैठक दिनांक 09.02.2012 में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया । यू.आई.डी. के संबंध में कार्ययोजना के अप्राप्त होने के संबंध में प्रमुख सचिव खाद्य द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में आधार योजना का कार्य राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) परियोजना के अंतर्गत एकत्र किये जाने वाले बायोमेट्रिक डेटा के आधार पर किया जाना है । राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के अंतर्गत उक्त कार्य हेतु भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एजेंसी नियत करने की कार्यवाही की जा रही है । तदोपरान्त कार्य प्रारंभ होने के बाद राशि का उपयोग किया जा सकता है । समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि राशि को समर्पित न किया जाये ।

(कार्यवाही सचिव, खाद्य विभाग)

सांख्यिकी प्रणाली में सुधार (योजना विभाग) की कार्ययोजनाएं समिति की पिछली बैठक में अनुमोदित की जा चुकी है । सचिव, योजना विभाग द्वारा समिति को यह अवगत कराया गया कि कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिए स्वीकृत पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया जा चुका है । मुख्य सचिव द्वारा भर्ती की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के लिए निर्देश दिये गये ।

(कार्यवाही योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग)

एजेण्डा कमांक-2. भारत सरकार से वर्ष 2011-12 में प्राप्त होने वाला अनुदान एवं विमुक्त राशि के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति-

समिति द्वारा भारत सरकार से वर्ष 2011-12 में प्राप्त होने वाला अनुदान एवं विमुक्त राशि के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति की समीक्षा की गई । मुख्य सचिव द्वारा समिति के सभी सदस्यों को वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राथमिकता पर अविलम्ब वित्त विभाग को भेजने के निर्देश दिये गये ताकि भारत सरकार से वर्ष 2011-12 की शेष राशि एवं वर्ष 2012-13 में देय राशि प्राप्त हो सके ।

वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के अनुमोदित शेष कार्यो की यथा आवश्यक प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये ताकि राशि का शीघ्र उपयोग किया जा सके ।

मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गए कि वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की जानकारी त्रैमासिक एवं वार्षिक आधार पर वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जावें ताकि समिति की अगली बैठक में इसकी समीक्षा की जा सके ।

(कार्यवाही पंचायत एवं ग्रामीण विकास/वन/गृह/जेल/वित्त/आवास एवं पर्यावरण/राजस्व/नगरीय प्रशासन एवं विकास/महिला एवं बाल विकास/ योजना आर्थिक एवं साख्यिकी/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/सामान्य प्रशासन/संस्कृति/खाद्य विभाग)

एजेण्डा कमांक-3. विभागों से प्राप्त कार्ययोजनाओं का अनुमोदन :-

वित्तीय वर्ष 2012-13 में विभिन्न विभागों से प्राप्त कार्ययोजनाओं पर भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के आधार पर समिति द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

(1) क्षमता निर्माण (राजस्व विभाग) :-

वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु कुल ₹ 4.00 करोड़ के विभागीय कार्ययोजना (परिशिष्ट-01) का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया । मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गए कि कार्ययोजना संबंधी जो कार्य अन्य विभाग जैसे कि चिप्स, सामान्य प्रशासन विभाग, लोक निर्माण विभाग आदि द्वारा किये जा सकते हैं, वे कार्य तत्काल इन विभागों को सौंप कर भारत सरकार से वर्ष 2010-11 में प्राप्त ₹ 4.00 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जावे । कार्ययोजना के क्रियान्वयन यदि किसी प्रकार की कठिनाई हो तो आपदा प्रबंधन संबंधी नई दिल्ली एवं रूड़की में स्थित संस्थान से विभागीय सचिव आवश्यक मार्ग दर्शन प्राप्त करें ।

(कार्यवाही राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग)

(2) पंचायत निकायों को अनुदान :-

विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई वर्ष 2012-13 की ₹ 397.70 करोड़ **(परिशिष्ट -2)** की कार्ययोजना का अनुमोदन समिति द्वारा किया गया । मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि पेयजल की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जावे । वर्षा ऋतु के पूर्व के समय का पूर्ण उपयोग कर कार्ययोजना के कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न/सम्पादित किया जाए । यह भी निर्देश दिये गये कि अभी तक भेजे गये उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं भविष्य में भेजे जाने वाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में राशि किन-किन मदों में व्यय की गयी है, का संपूर्ण एवं विस्तृत विवरण उपलब्ध करया जावे ।

(कार्यवाही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

(3) <u>सडक एवं पुलों का संधारण</u> :- वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों के नियमित संधारण तथा सतह नवीनीकरण हेतु ₹ 82.96 करोड़ (**परिशिष्ट** -3) की कार्ययोजना का अनुमोदन समिति द्वारा किया गया ।

(कार्यवाही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

(4) <u>नगरीय निकायों को अनुदान</u> :-

विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई वर्ष 2012-13 की ₹ 97.21 करोड़ (**परिशिष्ट** -4) की कार्ययोजना का अनुमोदन समिति द्वारा किया गया ।

(कार्यवाही नगरीय प्रशासन विकास विभाग)

(5) <u>सांख्यिकी प्रणाली में सुधार</u> :-

विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक के ₹ 16.20 करोड़ (**परिशिष्ट** -5) की संशोधित कार्ययोजना तथा वर्ष 2012-13 की वार्षिक कार्ययोजना हेतु ₹ 3.62 करोड़ का अनुमोदन समिति द्वारा किया गया ।

(कार्यवाही योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)

(6) <u>नया रायपुर का विकास</u> :-

विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2012-13 की वार्षिक कार्ययोजना ₹ 137.50 करोड़ (**परिशिष्ट** -6) का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाही आवास एवं पर्यावरण विभाग)

(7) <u>पुलिस प्रशिक्षण एवं पुलिस आवासीय गृहों का निर्माण</u> :-

विभागीय कार्ययोजना - (**परिशिष्ट** -7) अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों हेतु 108 आवास एवं आरक्षक/प्रधान आरक्षक के 526 आवास हेतु कुल ₹ 62.54 करोड़ एवं पुलिस अकादमी चंदखुरी तथा जंगल वारफेयर कॉलेज कांकेर में पुलिस प्रशिक्षण हेतु भवनों के निर्माण आदि मद में ₹ 10.50 करोड़ सहित कुल वार्षिक कार्ययोजना 2012-13 हेतु ₹ 73.00 करोड़ का अनुमोदन समिति के द्वारा किया गया ।

(कार्यवाही गृह विभाग)

(8) <u>कारागर अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण</u> :-

विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2012-13 हेतु ₹ 37.50 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना (**परिशिष्ट-8**) का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाही जेल विभाग)

(9) <u>स्वास्थ्य अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण</u> :-

यह निर्णय लिया गया कि कार्ययोजना में कम से कम 20 प्रतिशत राशि मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत अधोसंरचना निर्माण हेतु प्रावधान करने की आवश्यक कार्यवाही हेतु स्वास्थ्य विभाग को अधिकृत किया जाये । तदनुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा संशोधित कार्ययोजना वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

(कार्यवाही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

(10) <u>पुरातत्व संरक्षण</u> :-

विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2012-13 की वार्षिक कार्ययोजना ₹ 11.25 करोड़ **(परिशिष्ट -09)** का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया ।

मुख्य सचिव द्वारा विभाग को यह अधिकृत किया गया कि विभाग कार्ययोजना में आंशिक संशोधन आवश्यकतानुसार कर सकता है ।

(कार्यवाही संस्कृति विभाग)

(11) <u>आंगनबाड़ी भवन का निर्माण</u> :-

विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2012-13 की वार्षिक कार्ययोजना ₹ 37.50 करोड़ **(परिशिष्ट -10)** का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया ।

विभागीय कार्ययोजना में 833 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण का प्रावधान रखा गया है । प्रति आंगनबाड़ी भवन की लागत ₹ 4.50 लाख रखी गई है ।

(कार्यवाही महिला एवं बाल विकास विभाग)

(12) **प्रशासन अकादमी का निर्माण**

समिति द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रशासन अकादमी के निमाण हेतु वर्ष 2012-13 ₹ 7.00 करोड़ की कार्ययोजना <u>(परिशिष्ट-11)</u> का अनुमोदन समिति द्वारा किया गया ।

(कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग)

(13) <u>वन संरक्षण</u> :-

विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2012-13 की वार्षिक कार्ययोजना ₹ 102.78 करोड़ **(परिशिष्ट -12)** का समिति द्वारा अनुमोदन इस शर्त पर किया गया कि विभाग कार्ययोजना का घटकवार विवरण मापदण्ड सहित वित्त विभाग को उपलब्ध करायेगा ।

(कार्यवाही वन विभाग)

<u>एजेण्डा कमांक-4. विभागों से प्राप्त संशोधित कार्ययोजनाओं का अनुमोदन :-</u>

(1) <u>कारागर अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण</u> :-

विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 के अनुमोदित कार्ययोजना ₹ 37.50 करोड़ में प्रदेश की तीन जिलों कमशः जिला जेल कांकेर, जशपुर एवं उप जेल सूरजपुर में आर.सी.सी. डबल वाल के निर्माण कार्य का प्रावधान के स्थान पर <u>परिशिष्ट -13</u> में उल्लेखित ₹ 12.59 करोड़ के प्रस्ताव का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाही जेल विभाग)

(2) <u>स्वास्थ्य अवसंरचना का सुदृढीकरण</u> :-

विभाग के वर्ष 2011-12 के अनुमोदित कार्ययोजना में कुम्हाली विकासखण्ड जिला बस्तर में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई थी । इसके स्थान पर कुम्हाली विकासखण्ड के स्थान पर ग्राम कुम्हली विकासखण्ड लोहाण्डीगुड़ा जिला बस्तर में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु कार्ययोजना में संशोधन का अनुमोदन समिति द्वारा किया गया ।

(कार्यवाही लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

(3) <u>कर्मचारी एवं पेंशन डेटाबेस</u> :-

इस मद में 5 साल की अवधि हेतु ₹ 10.00 करोड़ के कार्ययोजना का अनुमोदन समिति द्वारा किया गया था । विभाग द्वारा इसे संशोधित करते हुए वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक का ₹ 3.24 करोड़ का संशोधित कार्ययोजना के संबंध में यह निर्देश दिये गये की राशि ₹ 10.00 करोड़ के संशोधित कार्ययोजना ही समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जावें ।

(कार्यवाही वित्त विभाग)

(4) <u>पुलिस प्रशिक्षण</u> :-

वर्ष 2011-12 के अनुमोदित कार्ययोजना में जंगलवार फेयर कालेज कांकेर हेतु ₹ 420.00 लाख के अंतर्गत अन्य कार्यो के साथ-साथ प्रशिक्षुओं हेतु दो नग हास्टल निर्माण कार्य हेतु ₹ 330.00 लाख का प्रावधान था, जिसके स्थान पर 170 प्रशिक्षुओं हेतु 01 नग कंपोजिट हास्टल के निर्माण कार्य हेतु ₹ 322.00 लाख की कार्योत्तर स्वीकृति समिति द्वारा दी गई ।

(कार्यवाही गृह विभाग)

मुख्य सचिव द्वारा यह निर्देश दिए गए कि वर्ष 2012-13 के लिए प्रस्तावित कार्ययोजना में सम्मिलित कार्यो के प्राक्कलन तैयार करने एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही तत्काल कर ली जाए, ताकि भारत सरकार से अनुदान राशि प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ किया जा सके ।

(कार्यवाही समस्त विभाग)

अंत में अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई ।

(मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित)

10/5/2012

(डॉ. ए.के. सिंह)
सदस्य सचिव

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची

1.	श्री विवके ढांड	–	प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
2.	श्री डी.एस मिश्र	–	प्रमुख सचिव, वित्त एवं योजना विभाग
3.	श्री एन.के.असवाल	–	प्रमुख सचिव, गृह एवं जेल विभाग
4.	श्री एन.बैजेन्द्र कुमार	–	प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग
5.	श्री एस.के.कुजूर	–	प्रमुख सचिव, वन विभाग
6.	श्री आर.पी.मंडल	–	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग
7.	श्री के.डी.पी. राव	–	सचिव, संस्कृति विभाग
8.	श्री सुब्रत साहू	–	सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग
9.	श्री विकास शील	–	सचिव, खाद्य विभाग
10.	श्री अमन सिंह	–	सचिव, ऊर्जा विभाग
10.	श्री बी.एल.अग्रवाल	–	सचिव, राजस्व विभाग
11.	श्री बिजयेन्द्र	–	सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
12.	श्री पी.सी. मिश्रा	–	सचिव, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी
13.	श्री एस.एस. बजाज	–	विशेष सचिव, आवास एवं पर्यावरण

विभागाध्यक्ष कार्यालय

1.	श्री अनील नवानी	–	महानिदेशक, पुलिस
2.	श्री गिरधारी नायक	–	अति. महानिदेशक, जेल
3.	श्री अवध बिहारी	–	आयुक्त कोष लेखा एवं पेंशन
4.	श्री सोनमणी बोरा	–	आयुक्त, छ.ग. गृह निर्माण मंडल
5.	श्री संजय पिल्ले	–	महानिरीक्षक, पुलिस
6.	श्री पी.के. जनवदे	–	प्रमुख अभियंता लोक निर्माण
7.	सुश्री अल्पना घोष	–	संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन

परिशिष्ट- 01

FORMAT-II

GRANT-IN-AID FOR CAPACITY BUILDING FOR DISASTER RESPOSNE

Annual Work plan for 2012-13: Finance & Physical

Name of the State : Chhattisgarh

Si. No.	Item/area of activities	Amount (in Lakhs)	Physical achievement at the end of the year	Remarks
1	**Main Activity : Research & Development**	**75.00**		
	i) Consultancies ralated to Disaster Risk Reduction in the State.	25.00	The Second Phase of Project Will be Completed.	
	ii) Hazard Risk Vulnerability Analysis (All District)	25.00	The Second Phase of Project Will be Completed.	
	iii) Consultancies for setting up of effective decision support system	25.00	Non Special data collection will be initited.	
2	**Main Activity : Equipped & Prepared/Strengthening of Disaster Response and Information Centres**	**100.00**		
	i) Procurement of equipment for the State & District Disaster Response and Information Centre (EOC)	100.00	All tahsil level Disaster Response & Information Centres will be Operational.	
3	**Main Activity :** Setting up of C.G. State Disaster Management Institute-Preparation of Detailed Project Report for setting up the Centre	**65.00**	Formulation of the State Disaster Management Institute Chhattisgarh.	
4	**Main Activity : Awarness Generation** i) Sensitisation meetings/ IEC meterials/ audio-visual/advertisement etc.	**10.00**	i) 10 rounds of Advertisements on dos and donts on Floods in newspapers and TV throughout the Flood season. ii) 10 rounds of Advertisements on Fire through print and audio visual media.	
5	**Main Activity :** Capacity Building, Training and Education including foreign training	**85.00**		
	i) School Safety : a) Preparation of School & College DM Plans, Mock drills once in a year b) Safety Audit of Sc	20.00	Traing of 5000 teachers on School Safety in 1000 Sch[illegible] and safety plan development @ 500 school x 18 distr[illegible]s	

	ii) Disaster Preparedness of Hospitals a) Preparation of Mass casualty Management Plans for the Medical College Hospitals b) Training of Doctors, Nurses, Paramedicals, Med	20.00	Traing of 100 doctors on Hospital Preparedness & Mass Casualty Management, 50 doctors on Trauma Management and 100 Paramedics on Mass Casualty handling. Training of Safety audit of all 18 districts hospitals and 3 Medical Colleges hospitals.	
	iii) Training on Earthquake Resistant Construction Techniques a) Training of Engineers/Architects on earthquake resistant tachniques	20.00	Traing of 200 government engineers and 100 Architect from Government & Private Sector will be trained on Earthquake resistant technology. 200 Masons will be trained on Earthquake resistant technology & safe Construction Practices.	
	iv) Training on Urban and Rural Fire Safety Management a) Training of Fireman on Urban Fire b) Preparation of Demo kit for mason training by leading Bhilai Steel Plant Fire Service.	25.00	This State is planning to established a New Fire Service under the Director General of Home Guard. Prepartion of State Fire Service Plan and active District Fire Service Plan. 500 Home Guard Jawan will be trained on Fire Fighting and Fire Management. Training given by Bhilai Steel Plant Bhilai Fire Service. Mock drill and workshop organization of mock drill , workshop and establishment of **Simulator** building for fire.	
6	**Main Activity : Preparation of Disaster Management Plan at District Level**	**20.00**	18 DDMP disaster management plan prepared and will be updated regularly.	
	i) Preparation DDMPs			
7	**Main Activity : Community Based Disaster Preparedness**	**20.00**		
	a) Training of Volunteers by Homeguard/police training institute at Chandkhuri raipur C.G.	10.00	Traing of 450 Volunteers on search and rescue and first aid	
	b) Training of Volunteers on First Aid, Search & Rescue through Homegard	10.00		
8	**Main Activity : Workshops & Conferences**	**25.00**	1 Number of State lavel workshop will be conducted on the different Hazards.	
	a) State Level workshop/conference on i) Flood & Fire	15.00		
	b) State Level Workshop/conference on i) Drough Management	10.00		
	Total	**400.00**		

परिशिष्ट – 02

तेरहवें वित्त आयोग वर्ष 2012-13 अन्तर्गत प्राप्त होने वाले कुल प्रावधानित अनुदान राशि का विवरण

(राशि ₹ करोड में)

वर्ष	सामान्य क्षेत्र मूल अनुदान	विशेष क्षेत्र मूल अनुदान	सामान्य क्षेत्र परफारमेन्स अनुदान	विशेष क्षेत्र परफारमेन्स अनुदान	योग
1	2	3	4	5	6
2012-13	210.84	21.10	144.66	21.10	**397.70**

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार वर्ष 2012–13 में राज्य को सामान्य क्षेत्र मूल अनुदान रूपये 210.84 करोड़, विशेष क्षेत्र मूल अनुदान रूपये 21.10 करोड़, सामान्य क्षेत्र परफारमेन्स अनुदान रूपये 144.66 करोड़ एवं विशेष क्षेत्र परफारमेन्स अनुदान रुपये 21.10 करोड़, कुल रुपये 397.70 प्रावधानित है। उक्त प्रावधानित अनुदान प्राप्त करने के लिए वित्त आयोग की निम्नानुसार आवश्यक शर्तो का पालन अनिवार्यतः किया जायेगा –

1- पंचायतों में "प्रिया साफ्ट" साफ्टवेयर में लेखा संधारण की कार्यवाही निरन्तर किया जाना आवश्यक है। भारत सरकार एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियमित समीक्षा की जा रही है।

2- प्रदेश के मुख्य बजट में पंचायती राज संस्थाओं के लिए पृथक से अनुपूरक बजट बनाया गया है, अतः त्रिस्तरीय पंचायतों के लेखों के अंकेक्षण का कार्य करने हेतु स्थानीय संपरीक्षा विभाग के साथ–साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक भी अधिकृत है।

3- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखों के अंकेक्षण कार्य सम्पादन के समय गत वर्ष के लेखो का संशोधित 08 डाटा फार्मेट में जानकारी उपलब्ध कराना होगा।

4- तेरहवें वित्त आयोग अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि निर्धारित समयावधि में पंचायतों के बैक खाते में अन्तरण किये जाने की कार्यवाही जिला पंचायतों द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

योजनान्तर्गत सामान्य क्षेत्र परफारमेन्स अनुदान एवं विशेष क्षेत्र परफारमेन्स अनुदान वर्ष 2012–13 में प्राप्त होना प्रावधानित है। अतः त्रिस्तरीय पंचायतों को प्राप्त अनुदान राशि अनुसार वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर निर्धारित मदवार व्यय किया जाय। जिससे भारत सरकार द्वारा दोनों परफारमेन्स अनुदान राज्य शासन को शत–प्रतिशत अदाय किया जायेगा।

अपर संचालक
पंचायत एवं समाज सेवा
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिशिष्ट–" "

तेरहवें वित्त आयोग अन्तर्गत
सामान्य क्षेत्र मूल अनुदान एवं विशेष क्षेत्र मूल अनुदान
की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2012-13
(जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत)

प्रति जिला पंचायत औसत राशि ₹ 50 लाख से 01 करोड़
प्रति जनपद पंचायत औसत राशि ₹ 30 से 50 लाख

(राशि ₹ करोड में)

क्र.	मद	सामान्य क्षेत्र मूल अनुदान	विशेष क्षेत्र मूल अनुदान	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	स्वास्थ्य	22.15	2.20	35%
2	पेयजल	9.50	0.95	15%
3	शिक्षा	6.30	0.65	10%
4	पोषण	3.15	0.30	5%
5	विकास एवं अधोसंरचना कार्य	15.20	1.80	26%
6	समाज कल्याण	1.30	0.20	2%
7	विद्युत/सौर ऊर्जा	1.90	0.20	3%
8	प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट निधि	3.15	-	3%
9	प्राकृतिक आपदाओं हेतु सुरक्षित निधि	0.60	-	1%
योग :–		**63.25**	**6.30**	**100%**

विशेष क्षेत्र मूल अनुदान के लिये वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2012–13 में प्रस्तावित राशि का व्यय केवल अनुसूचित क्षेत्रों के विकास कार्यो में ही किया जायेगा।

अपर सचालक
पंचायत एवं समाज सेवा
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिशिष्ट–" "

तेरहवें वित्त आयोग अन्तर्गत
सामान्य क्षेत्र मूल अनुदान एवं विशेष क्षेत्र मूल अनुदान हेतु
जिला/जनपद पंचायतों के लिये वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2012-13

जिला/जनपद पंचायत स्तर पर प्रावधानित राशि ₹ 69.55 करोड़

तेरहवें वित्त आयोग वर्ष 2012–13 की अनुशंसा अनुदान अन्तर्गत जिला पंचायतों को प्राप्त होने वाले 10% आबंटन एवं जनपद पंचायतों को प्राप्त होने वाले 20% आबंटन से स्वीकृत किये जाने वाले कार्यो की कार्ययोजना निम्नानुसार है –

1- स्वास्थ्य :–

जिला एवं जनपद पंचायत को कुल प्राप्त आबंटन के 35% निधि से जिला/जनपद पचांयत के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों में बिजली/पानी/शौचालय सुविधा/ बीमार व्यक्तियों के परिजनों के रुकने हेतु अतिरिक्त कक्ष निर्माण/भोजन शेड निर्माण कार्य/ पेयजल शुद्धिकरण उपकरण/दवाई। सार्वजनिक स्थलों/भवनों में शौचालय मूत्रालय निर्माण/हाईस्कूल स्तर तक शालाओं में शौचालय सुविधा/पेयजल सुविधा/ पेयजल शुद्धिकरण उपकरण/पूर्व में उपलब्ध अधोसंरचनाओं का रखरखाव।

पेयजल :–

जिला एवं जनपद पंचायत को कुल प्राप्त आबंटन के 15% निधि से जिला/जनपद पचांयत के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामों में हैण्ड पम्पों के प्लेटफार्म्स का निर्माण/मरम्मत, हैण्ड पम्प के सुधार की सामान्य सामग्री, सोख्ता गड्ढों, वाटर रिचार्ज संरचना का निर्माण कार्य। पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के पाइप, ग्राम में जल निकासी हेतु नाली निर्माण, नलयुक्त प्लास्टिक टंकी लगाकर सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल उपलब्ध कराना, ग्रामों में नलजल सुविधा बढ़ाने के कार्य/हैण्डपंपों में विद्युत पंप लगाना/पाईप लाईन बढ़ाने एवं लगाने के कार्य। बाजारों में पेयजल सुविधा। निस्तार के जल स्त्रोतों का संधारण/छोटे नालों में कम लागत की पानी रोकने वाली संरचना का निर्माण/पूर्व में संचालित योजनाओं का संधारण।

3- शिक्षा :–

जिला एवं जनपद पंचायत को कुल प्राप्त आबंटन के 10% निधि से जिला/जनपद पचांयत के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामों में प्राथमिक/माध्यमिक शाला भवनों का संधारण कार्य/ कन्या शालाओं/आश्रम शालाओं में अतिरिक्त कक्ष एवं आहाता निर्माण/प्राथमिक/ माध्यमिक शाला छात्रावास भवनों में आवश्यक रखरखाव एवं भवन मरम्मत/बिजली पानी की सुविधा/वाचनालय की पुस्तकें/छात्रावास में भोजन बनाने, खाने के उपकरण/ छात्रावासियों के लिए के खेल उपकरण/कम लागत के छोटे खेल मैदान निर्माण/शालाओं में शिक्षण सामग्री/छात्रावास/प्रयोग शालाओं में उपकरण। विशेष क्षेत्र के लिए उपलब्ध निधि से अजजा वर्ग के प्राथमिक शालाओं के बच्चों को पठन पाठन सामग्री का प्रदाय भी किया जा सकेगा।

4- पोषण :-

जिला एवं जनपद पंचायत को कुल प्राप्त आबंटन के 5% निधि से जिला/जनपद पचांयत के ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी भवन में किचन शेड निर्माण/ बच्चों के बैठने/खेलने के उपकरण, प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में किचन शेड निर्माण/ बच्चो के लिये खाना बनाने, परोसने, बैठने की सामग्री एवं मध्यान्ह भोजन बनाने हेतु रसोई गैस उपकरण (जहॉ रिफिलिंग की सुविधा हो) का प्रदाय। ऑगनबाड़ी केन्द्रों का वार्षिक रखरखाव एवं सुधार, विद्युतीकरण, शुद्ध पेयजल रखने एवं पेयजल शुद्धिकरण के उपकरणों का प्रदाय। पूर्व से संचालित योजनाओं के रखरखाव का कार्य।

5- अधोसंरचना निर्माण/विकास कार्य :-

जिला एवं जनपद पंचायत को कुल प्राप्त आबंटन के 26% निधि से जिला/जनपद पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत से पूर्व निर्मित परिसम्पत्तियों का रखरखाव/उचित मूल्य की दुकान सह गोदाम निर्माण/खाद्य भण्डारण गोदाम/सी.सी.रोड निर्माण/नाली निर्माण, पंचायत मुख्यालय सें आश्रित ग्रामों को जोड़ने वाले प्रथम श्रेणी मार्ग निर्माण एवं उसमें छोटे पुल-पुलिया का निर्माण/सामुदायिक भवन निर्माण/यात्री प्रतीक्षालय, रंगमंच, चबूतरा, मंगल भवन, कांजी हाऊस भवन, तालाबों में घाट निर्माण, व्यावसायिक परिसर एवं दुकान निर्माण। चीरघर के पास शेड निर्माण/ मुक्तिधाम के पास शेड निर्माण, लघु वनोपज संग्रहण के छोटे गोदाम (तेन्दूपत्ता नही)। बाजारों में नाली निर्माण, बाजार शड निर्माण/बाजार स्थल में कॉक्रीटीकरण/ आमजनों के बैठने के लिए शेड निर्माण/पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने वाले कार्य ।

6- समाज कल्याण :-

जिला एवं जनपद पंचायत को कुल प्राप्त आबंटन के 2% निधि से जिला/जनपद पचांयत के ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रितों/निःशक्तों के लिए रहवासी सुविधा, निशक्त छात्र-छात्राओं के लिये उपकरण/कृत्रिम अंग, शैक्षणिक सामग्री, रैम्प का निर्माण। पूर्व से संचालित योजनाओं का रखरखाव।

7- सौर ऊर्जा/विद्युत ऊर्जा :-

जिला एवं जनपद पंचायत को कुल प्राप्त आबंटन के 3% निधि से जिला/जनपद पचांयत के ग्रामीण क्षेत्रों में अनु.जाति/अनुसूचित जन जन जाति के लघु/सीमांत कृषकों के पंपों ऊर्जाकरण हेतु लाईन विस्तार कार्य, गलियों/ सार्वजनिक स्थलों में प्रकाश व्यवस्था, सोलर लाईट लगाना। पूर्व से योजनाओं में निर्मित आस्तियों का रखरखाव।

8- प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट :-

जिला पंचायत को कुल आबंटित निधि में से 4% राशि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए व्यय की जा सकेगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हेतु आरक्षित निधि का 1% राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के व्यय के लिए जिला पंचायत में सुरक्षित रखा जायेगा। जिला पंचायत शेष 3% निधि का उपयोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिये व्यय कर सकेंगी।

जनपद पंचायत को आबंटित निधि से जनपद पंचायतें 4% प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट पर व्यय कर सकेंगी।

प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मद अन्तर्गत कार्यालयीन व्यय, कम्प्यूटर प्रिन्टर क्रय, कम्प्यूटर प्रिन्टर सामग्री, फर्नीचर, 13वें वित्त आयोग के कार्यालयीन कार्य/डाटा एन्ट्री के लिए मानदेय व्यय, लेखा संधारण पर आऊट सोर्सिंग व्यय, भ्रमण व्यय, प्रशिक्षण व्यय, परामर्शदात्री सेवाओं पर व्यय, लेखा संधारण व्यय, लेखाओं के कम्प्यूटराईजेशन पर किया जा सकेगा।

:- <u>प्राकृतिक आपदाओं हेतु सुरक्षित निधि</u> :--

जिला पंचायत/जनपद पंचायत को प्राप्त निधि की 1% राशि सुरक्षित निधि के रूप में जिला/जनपद पंचायत स्तर पर रखी जायेगी, जो पंचायत क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने बाढ, सूखा, बिजली गिरने, जंगली जानवरों द्वारा घायलों के प्रारंभिक उपचार, संक्रामक बीमारियों से रोकथाम के उपाय, आगजनी से प्रभावितों को तत्काल जीवनोपयोगी सामग्री उपलब्ध कराने/पुनर्वास के लिए आरक्षित होगी।

इस निधि का उपयोग जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं संबंधित जिला पंचायत के अध्यक्ष के परामर्श पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष में इस प्रयोजनों में व्यय न होने पर आगामी वित्तीय वर्ष में सुरक्षित निधि का उपयोग अधोसंरचना विकास मद में किया जा सकेगा।

विशेष क्षेत्र मूल अनुदान अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि का उपयोग उपरोक्त वर्णित कार्यो के लिये अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों के कार्यो पर निर्धारित प्रतिशत के अनुरूप किया जा सकेगा।

अपर संचालक
पंचायत एवं समाज सेवा
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिशिष्ट–"[illegible]"

तेरहवें वित्त आयोग अन्तर्गत
सामान्य क्षेत्र मूल अनुदान एवं विशेष क्षेत्र मूल अनुदान हेतु
ग्राम पंचायतों के लिये वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2012-13

ग्राम पंचायत स्तर पर प्रावधानित राशि ₹ 162.36 करोड़

तेरहवें वित्त आयोग वर्ष 2012-13 की अनुशंसा अन्तर्गत राज्य को प्राप्त होने वाले कुल अनुदान का 70 प्रतिशत ग्राम पंचायत को आबंटित किया जायेगा। औसतन प्रति ग्राम पंचायत राशि रुपये 1.00 से 1.50 लाख अनुमानित प्राप्त होगा।

योजनांतर्गत ग्राम पंचायतें वार्षिक कार्ययोजना अनुसार ग्राम सभा के अनुमोदन से कार्य स्वीकृत कर सकेंगे।

योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र के भीतर निम्नानुसार कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर कार्ययोजना में सम्मिलित करेंगे –

अ. ग्रामों में स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उपायों को संबंधी कार्यो को सर्वाधिक प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत कर पूर्ण किया जाना।

ब. ग्रामों में ऐसे कार्य लिये जाये जो कम लागत के, शीघ्र पूर्ण कराये जाने वाले एवं ग्रामीणजनों को लाभ पहुँचाने वाले हों।

स. ग्राम पंचायतों द्वारा निम्नानुसार कार्य स्वीकृत किये जायेंगे –

1- ग्राम पंचायतों का लेखा संधारण एवं लेखाओं का कम्प्यूटराईजेशन :–

ग्राम पंचायतें वित्त आयोग से प्राप्त सामान्य अनुदान से प्राप्त निधि का अधिकतम 10% ग्राम पंचायतों का लेखा संधारण एवं लेखाओं का कम्प्यूटराईजेशन पर व्यय कर सकेंगी। इसमें 13वें वित्त आयोग के कार्यालयीन कार्य के लिए स्टेशनरी व्यय, पचांयतों के प्रिया साफ्ट में लेखा संधारण के लिए डाटा एन्ट्री के लिए व्यय, लेखाओं के कम्प्यूटराईजेशन, अन्य कार्यालयीन व्यय, कम्प्यूटर प्रिन्टर सामग्री, फर्नीचर, आदि पर व्यय किया जा सकेगा।

2- ग्रामों मे स्वच्छ वातावरण प्रदान करने वाले कार्य :–

सार्वजनिक स्थलों/भवनों में शौचालय, मूत्रालय निर्माण, बी.पी.एल. परिवार वाले घरों में शौचालय निर्माण, पेयजल शुद्धिकरण उपकरण, ओ.आर.एस. पैकेट जैसी जीवनरक्षक दवाई। शालाओं में शौचालय सुविधा/पेयजल सुविधा/पेयजल शुद्धिकरण उपकरण/पूर्व में उपलब्ध अधोसंरचनाओं का रखरखाव।

3- ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने वाले कार्य :–

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामों में हैण्ड पम्पों के प्लेटफार्म्स का निर्माण/मरम्मत, हैण्ड पम्प के सुधार की सामान्य सामग्री, सोख्ता गड्ढों, वाटर रिचार्ज संरचना का निर्माण कार्य। पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के पाईप, ग्राम में जल निकासी हेतु नाली निर्माण, नलयुक्त प्लास्टिक टंकी लगाकर सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल उपलब्ध कराना, ग्रामों में नलजल सुविधा बढाने के कार्य/हैण्डपंपों में विद्युत पंप लगाना/पाईप लाईन बढ़ाने एवं लगाने के कार्य। बाजारों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना एवं लोगों के लिए छायादार स्थल का निर्माण। निस्तार के जल स्त्रोतों का संधारण। पूर्व में संचालित योजनाओं का संधारण।

4- <u>ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को शिक्षण सुविधा बढाये जाने के उपाय</u> :–

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामों में प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं का वार्षिक संधारण कार्य प्राथमिक/माध्यमिक शाला आवश्यक रखरखाव एवं भवन मरम्मत/बिजली पानी की सुविधा/वाचनालय की पुस्तकें/मध्यान्ह भोजन बनाने हेतु उपकरण, खाना खाने हेतु बरतन/छात्रों के लिए खेल उपकरण, शालाओं में शिक्षण सामग्री/छात्राओं की शालाओं में उनके बैठने की व्यवस्था,आदि कार्य लिये जा सकते हैं। विशेष क्षेत्र के लिए उपलब्ध निधि से अजजा वर्ग के प्राथमिक शालाओं के बच्चों को पठन–पाठन सामग्री का प्रदाय भी किया जा सकेगा।

5- <u>ग्रामीण क्षेत्र के 06 वर्ष तक के बच्चों के लिए पोषण</u> :–

ग्रामीण क्षेत्रों की आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन में किचन शेड निर्माण/बच्चों के बैठने/खेलने के उपकरण, बच्चो के लिये खाना बनाने, परोसने, बैठने की सामग्री का प्रदाय। ऑगनवाडी केन्द्रों का वार्षिक रखरखाव एवं सुधार, विद्युतीकरण, ऑगनवाडी में शुद्ध पेयजल रखने एवं पेयजल शुद्धिकरण के उपकरणों का प्रदाय। पूर्व से संचालित योजनाओं के रखरखाव का कार्य।

6- <u>अधोसंरचना निर्माण/विकास कार्य</u> :– ग्राम पंचायतों में पूर्व से निर्मित परिसिम्पत्तियों का रखरखाव/उचित मूल्य की दुकान सह गोदाम निर्माण/सी.सी.रोड निर्माण/नाली निर्माण, पंचायत मुख्यालय सें आश्रित ग्रामों को जोड़ने वाले मार्ग निर्माण एवं उसमें छोटे पुल–पुलिया का निर्माण यात्री प्रतीक्षालय, रंगमंच, चबूतरा, तालाबों में घाट निर्माण, बाजारों में नाली निर्माण, बाजार शेड निर्माण/बाजार स्थल में कॉक्रीटीकरण/ आमजनों के बैठने के लिए शेड निर्माण कार्य, ग्राम की गलियों में विद्युत लाईन विस्तार कार्य, गलियों/सार्वजनिक स्थलों में प्रकाश व्यवस्था, सोलर लाईट लगाना आदि कार्य लिये जा सकते हैं।

7- <u>प्राकृतिक आपदाओं हेतु सुरक्षित निधि</u> :– ग्राम पंचायतें उन्हें प्राप्त निधि में से अधिकतम रूपये 5000.00 (रूपये पॉच हजार मात्र) या अनुदान का पांच प्रतिशत, ग्राम में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने, संक्रामक बीमारियों से रोकथाम के उपाय, प्रभावितों को तत्काल जीवनोपयोगी सामग्री/खाद्यान्न उपलब्ध कराने/अस्थायी आवास बनाने के लिए आरक्षित रखेंगी। निधि का उपयोग ग्राम में किसी परिवार में अन्य कारणों से भोजन की उपलब्धता न होने पर तत्काल भोजन की व्यवस्था करने हेतु भी किया जा सकेगा। निधि का उपयोग ग्राम पंचायत के सरपंच/उपसरपंच/सचिव के निर्णय अनुसार किया जायेगा। आगामी ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में इसके व्यय विवरण प्रस्तुत कर व्यय का अनुमोदन कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष में इस प्रयोजनों में व्यय न होने पर आगामी वित्तीय वर्ष में सुरक्षित निधि का उपयोग विकास कार्यो में किया जा सकेगा।

अपर संचालक
पंचायत एवं समाज सेवा
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिशिष्ट-03

(लंबाई कि.मी. में, राशि लाख रू. में)

सं.कं.	जिले का नाम	सड़कों की संख्या	लंबाई	संधारण हेतु आवश्यक प्रस्तावित राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	बिलासपुर	27	101.83	767.67	
2	दुर्ग	15	58.98	560.35	
3	जांजगीर-चांपा	17	51.33	518.71	
4	कांकेर	24	80.88	790.22	
5	कवर्धा	27	121.65	1479.27	
6	महासमुन्द	12	49.55	570.28	
7	रायगढ़	22	115.18	876.57	
8	रायपुर	38	202.05	1945.55	
9	बलौदाबाजार	15	73.99	787.47	
योग		**197**	**855.44**	**8296.09**	

परिशिष्ट-04

प्रपत्र – घ

13 वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रावधानित राशि अनुसार वित्त वर्ष 2012–13 के लिये अनुमोदित कार्यों हेतु मांग

(राशि करोड़ रू. में)

S.No	Name of Project	Nagar Nigam	Nagar Palika	Nagar Panchayat	Total
1	**Solid Waste Management**	19.77	4.76	12.37	**36.90**
2	**Storm Water Drain**	20.78	4.85	2.08	**27.71**
3	**Water Supply**	8.70	8.81	6.63	**24.14**
4	**Sanitation and Other**	6.27	0.78	0.58	**7.63**
5	**Data Base/Data Center**	0.10	0.49	0.24	**0.83**
		55.62	**19.59**	**21.90**	**97.21**

आयुक्त
संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास
छत्तीसगढ़ रायपुर

Plan for 1st Installment

Works to be done:

(i) Listing of the State/district levels authorities meant for registration of legal entities with the complete official addresses and designation of the officer responsible for providing information.

(ii) Listing of the items of statutory information at the time of registration separately for each type of institution.

(iii) Development of database in electronic form for consolidation of all such information available.

On the basis of above expenditure plan the detail expenditure plan for 1st year is given below :-

At district level

Salary for supervisors	: 27xRs.15000 x 6month= Rs.24,30,000
Salary for investigators	: 50xRs10000 x 6month =Rs. 30,00,000
Traveling Allowances	: 77xRs.2000 x 6month =Rs. 9,24,000
Computer with UPS, AV etc	: 27xRs.50000 = Rs. 13,50,000 (one time)
Furniture	: 27 dist.x Rs.20000 = Rs. 5,40,000 (one time)
Photocopier	: 27 dist.xRs.100000=Rs27,00,000(one time)
Stationery	: 27 dist.x Rs.100000 = Rs. 27,00,000
Miscellaneous	: 27 dist.x Rs.30000 = Rs. 8,10,000

As per above mentioned provisions along with other activities a sum of Rs. **144.54** lakh is earmarked for all **27** districts during **2012-13.**

At State level

Similarly, **1** consultant and **2** investigators are proposed to be engaged at State HQ, so Rs. **5.24** lakh is allocated for the establishment cost. In this cost for the purpose of the Printing of Business registers and its formats/schedules and translation of instruction manuals into local languages and printing of sufficient copies will be done by state HQ. and the cost of Rs. **2.00** lakh is proposed for the same is included and for miscellaneous cost of Rs. **0.30** lakh is proposed additionally. Also Rs. **3.00** lakh is proposed at state HQ for suitable software development. It is also proposed to call a quarterly review meeting at state level to monitor the progress of various activities taken under TFC.

Training

To train newly recruited staffs (160) about various aspects of preparation of business register and methodology adopted to fulfill its objectives a two-day training program is proposed to be held at State level and it is also proposed to organize an orientation workshop for various stake-holders of the state to edify the purpose and utility of the Business Register. A sum of Rs. **3.20** lakhs is assigned for this purpose. The following officials will participate on this training program:-

- (50+2) 52 investigators + 27 Supervisors+counsultant 1 = 80 officials, which are newly recruited under this plan.
- 27 District officials, 3 officials from DES HQ = 30 officials' who are the state government's employee.
- Orientation Workshop for stakeholders at state level, around 40-50 Approx 45 Officials are supposed to attend the same.
- Training/Workshop programmes for stakeholders at district level.

(80 persons x 4 day = 320 days) & (per person training cost is 1000)

(80+75=155) (155 x 4 = 620) & 620 x 1000 =6,20,000 (6.20 lakhs)

Thus a sum of Rs. **14.44** lakh is assigned at state hq level activities.

Summing up, an amount of Rs. 158.98 lakhs is proposed towards preparation of Business Register during the year 2012-2013.

E:\13 fc folder\New Microsoft Office Excel 97-2003 Worksheet

III. Improvement of data in respect of Farm Activities.

Farm activity data is very essential for compiling GSDP and GDDP. The same is available with Commissioner of Land Records and Agriculture. However to coordinate and collect the data periodically from these two sources and also to supplement from other sources if required it is proposed to have a cell in each district. Collection of micro level data on important parameters required for GSDP may be collected quarterly/ annually in 3rd and 4th year from the samples drawn by adopting suitable statistical techniques.

Works to be done:

(i) *Identification of 10 major crops in the district and collection of estimates of cultivated area, production and peak period arrival prices at primary market for these crops, from either the existing administrative records or through studies to compile these data.*

(ii) *Conducting of cost of cultivation studies for important crops and their dissemination for the use of estimating district level Gross Value Added (GVA).*

(iii) *Collection of data on production and prices for Horticulture and other crops, either from the existing administrative records or conduct studies to compile it. Use of these data in estimation of District Income.*

To achieve the above milestones as per the guideline provided by MoSPI, it is proposed to have one field investigator (contract basis) at **22** smaller District and two at **5** bigger districts in respect to farm activity, with necessary infrastructure. The supervisors assigned for the Business Register will also monitor this activity. It is note that the salary provision for these investigators is made for 6 month only in the first year and for subsequent years 12 months salary provision has been made.

Expenditure Plan: Plan for 1st Installment

At district level

Salary for investigators	: 32personsxRs10000x6month =Rs. 19,20,000
Traveling Allowances	: 32 personsxRs.2000x6month =Rs.3,84,000
Stationery	: 27 dist.x Rs.50000 = Rs. 13,50,000
Miscellaneous	: 27 distxRs.30000 = Rs. 8,10,000

The provision has been made for collection and compilation of data such as cultivated area, yield estimates and price at primary markets of identified major crops. Thus, **Rs. 44.64 lakh** is earmarked for all 27 districts during the year of **2012-13.**

At State level

Similarly, **2** investigators (contract basis) are proposed to provide at State HQ with the same rate of establishment cost as per the District level and Rs. 5.00 lakhs is proposed for suitable software development. Thus, a sum of Rs. 11.14 lakh is allocated at state HQ.

Training

To train newly recruited staffs about various aspects of Farm activities a two day training program is proposed to be held at State level and it is also proposed to organize an orientation workshop for various concerning stake-holders of the state to edify the purpose and utility of the same. A sum of Rs. 2.40 lakhs is assigned for this purpose. The following officials will participate on this training program:-

- Newly engaged 23 investigators+ 18 Supervisors(BR) = 41 officials
- 18 District officials + 2 officials from DES HQ = 20 officials
- Orientation Workshop for stake-holders around 30 officials are supposed to attend the same.

Finally, Rs. 11.14 lakh is assigned for state level activities and Rs. 44.64 lakh is assigned for district level activities. Totally, an amount of Rs. 55.78 lakh is proposed for Collecting and compiling data in respect to form activities in the **year 2012-2013.**

IV. Pooling of NSS data at State and District level:

At present, the state has been participating in NSS in matching sampling basis. Though the fieldwork is being carried out in time, but the progress of data entry, validation, tabulation are delayed due to shortage of manpower and other infrastructures like computers, printers etc.. From the inception of this new state, no report also could be prepared and published mainly due to lack of expertise in this field. In addition, an programmer is required to be engaged who would oversee every day work, develops suitable program and run both DPD supplied programme as well as customized programme meant for DES.

The fund is proposed to be utilized to procure adequate nos. of computers and necessary software, to enhance manpower for data entry and finally to get the service of outside experts having experience in examining tables and comparing with central NSS table and report writing.

Though, as per 13th FC milestone, pooling of NSS data is earmarked for 3rd year, the activity needs to be started from very first year so that data can be entered, validated and table can be prepared. Both central and state data should be comparable which is the precondition for pooling the data.

Works to be done:

(i) Data of past rounds, viz., 62nd-67th rd, except 63rd rd, to be completed with priority. Data of ensuing rounds to be entered in 4 NSS units itself by utilizing the service of DEO

(ii) Data to be validated using DPD and/or customized software.

(iii) Tables to be generated and compared with NSS central data.

(iv) Survey data of respective NSSO rounds to be pooled; data to be compiled and report prepared.

(v) Use of pooled data on relevant parameters for compilation of district income estimates.

To achieve the milestone provided, it is proposed to have 5 data entry operator and one asst. programmer on contract basis at State HQ and one data entry operator to each of NSS unit namely Raipur, Durg, Bilaspur & Raigarh. It is further proposed to augment computing resource in first year only. As stated earlier an expert/ consultant is proposed to be engaged for each round to oversee the quality of data, comparing tables with central data and preparing reports on the basis of such tables. Year wise details are as follows:

Expenditure Plan:

Plan for 1st Installment

At district level

Salary for Data Entry Oper. : 4pers.xRs10000x6month =Rs. 2,40,000
Computer with UPS, AV etc : 4pers.xRs.50000 = Rs.2,00,000 (one time)
Furniture : 4pers.xRs.20000 = Rs. 80,000 (one time)
Stationery : 4 NSS unitxRs.50000 = Rs. 2,00,000
Miscellaneous : 4 nss unit xRs.30000 = Rs. 1,20,000

Total: Rs. 840000

Thus **Rs. 8.40 lakh** is earmarked for 4 NSS units during 2012-13.

At State level

Hiring Consultant : Rs. 3,00,000
Asst. Programmer's salary : 1*Rs20000*6month =Rs. 1,20,000
Travelling Allowance for AP : 1*Rs.5000*6month= Rs. 30,000
Salary for Data Entry Oper. : 5 xRs8500x6month =Rs. 2,55,000
Stationery : Rs. 3,00,000
Miscellaneous : Rs.37,000
Development of SW : Rs. 3,00,000
Training : Rs. 1,00,000

Total: Rs. 1442000

Thus, a sum of **Rs. 14.42 lakh** is allocated at State level during 2012-13.

Finally, Rs. 22.82 lakh is proposed for the NSS activities in **the year 2012-2013.**

V. Providing network connectivity among districts & StateHQ:

Plan for 1st Installment

13th FC desires to get network assessed at each district HQ and State DES and to operationalise the connectivity among these. This exercise will require the assessment of data load and extent of other activity DES is going to take up in future years. However, it is proposed to engage NIC/Other Govt. organization or private consultant to assess the network availability in each district and augment the system as the case may be. The hardware / software provisioned under this head will not be provisioned in CG-SSSP which is under preparation.

Expenditure Plan:

Works to be done:

(i) Assessment of the software and hardware requirements of the districts for connectivity with the State headquarters in a Wide Area Network.

(ii) Identification of existing hardware and software available in the Districts, integrating their use for the purposes specified under this grant. Purchase of any additional hardware items (to be kept to a minimum), only if explicitly approved by HLMC and the GOI group.

(iii) Operationalization of the connectivity of the State headquarters and all the district offices.

(iv) Development of applications suitable for transmission of district level data to state and national agencies for sharing of data.

At present 12 districts HQ have been connected through NIC network and 5 districts have other than NIC connection (i.e. broadband etc.) while only one district namely Narayanpur has no network connectivity. Thus it is proposed to get connected the remaining 6 districts through NIC network/SWAN. Presently State HQ is connected through BSNL-Broadband, so it is proposed that to establish NIC network at state HQ also.

To ensure the uninterrupted connectivity between State HQ and districts HQs it is proposed to have one assistant programmer @ 20000 per month on contract basis at State HQ and to augment computer and other necessary resources in 1st year itself. The provisions of Rs. 5000/month/district is made for expenses on telephone, fax, internet charges etc. Similarly, yearly provision of Rs. 20,000/ district for maintenance of network connectivity is also made.

Thus, Rs. 20.98 lakh is proposed for State HQ and Rs. 45.90 lakh for district HQ. Summing up, Rs. 66.88 lakhs is earmarked for providing uninterrupted network connectivity among districts and State headquarters.

VI. Training for capacity building:-

Chhattisgarh is a new state. During the last two years 101 technical staffs were recruited. Further, in coming three years, as a result of filling up of vacant post/newly sanctioned post, around 500 more technical staffs will be recruited to strengthen the statistical system of the state.

Technical staffs likely to be recruited in the next two years:-

Type of vacancy	Numbers
Post lying vacant at present with in DES	133
Post lying vacant at present with the line department	298
Newly created post	68

There is an urgent need to train the newly recruited staffs in all spheres of statistical activities.

Apart from this, the statistical personnel of different line departments need to be trained. Training will be imparted in State Institute of Rural Development (SIRD), Administrative training Institute (ATI) and Agriculture Training College (ATC) in absence of any training institute of DES's own. However, DES will coordinate for selection of resource persons. As many experts are not available at Raipur, experts will be invited from CSO, NASA, other related statistical organisations / institutes mostly located outside of Chhattisgarh to impart training. As the proposed training institutes are located more than 20 kms away from the city three vehicles will be required to pick up the experts from Railway stations/ Airport etc.

Training norms for a 5 days programme is as follows

Expenditure per day for following items are:-

- Training Hall charges :- Rs. 3000
- Breakfast , Lunch, Dinner : - Rs. 6000 for 30 participant@ Rs 200.
- Honorarium for trainers :- Rs 3000 (four experts)
- Transportation cost :- Rs 15000 (Three vehicles, TA to trainers)
- Arrangement for stay:- Rs 3000

Total Rs 30000

For five days: - Rs 30000 x 5= Rs 150000.

Apart from this for each course, following expenditure will be required:-

Stationary, training materials:- Rs. 750X30= Rs 22500

Miscellaneous:- Rs 7500

Total Rs 30000

Grand total for one week training course :- Rs 180000

There are **394** technical staffs in the DES and **523** in the line department. Thus, on an average, **12 training programmes** every year are proposed to be organized to train these staffs. Entire expenditure on training in each year is subject to availability of fund and requirement.

Thus Rs. 25.00 lakhs is proposed for the year 2012-13 under this activity.

Improvement of Statistical System at State & District Levels: - Proposed budget allocation activity for the year2012-13

(Rs. in lakh)

DES : Chhattisgarh			Training Orgnised by CSO : 1.80 crore	
Total Grant for Entire period: 18.00 crore			Grant for the State : Rs 16.20 crore	
S.N.	Name of the activities	I[st] Installment		
		State HQ	District	Total
1	Preparation of Business Register	14.44	144.54	**158.98**
2	Strengthening of Local Bodies	16.84	63.54	**80.38**
3	Improvement of data in respect of Form Activities	11.14	44.64	**55.78**
4	Pooling of Central and State sample data for generating district level parameters	14.42	8.40	**22.82**
5	Providing network connectivity among districts and State headquarters	6.00	13.50	**19.50**
6	Intensive/Refresher training programs or all technical staff (existing + new) is proposed (including Line dept.)	25.00	0.00	**25.00**
	Total	**87.84**	**274.62**	**362.46**

संशोधित कार्ययोजना

(परिशिष्ट)

Name of the activities	I[st] Installment	II[nd] Installment	III[rd] Installment	IV[th] Installment	Total
Preparation of Business Register	158.98	174.56	185.90	185.90	**705.34**
Sterngthening of Local Bodies	80.38	85.11	89.83	82.23	**337.15**
Improvement of data in respect of From Activities	55.78	82.96	87.04	79.84	**305.62**
Pooling of Central and State sample data for generating district level parameters	22.82	26.60	27.83	27.83	**105.08**
Providing network connectivity among districts and State headqutarters	19.50	16.30	15.54	15.54	**66.88**
Intensive/Refresher training programs of all technical staff (existing+new) is propopsed (including Line dept.)	25.00	25.00	25.00	25.00	**100.00**
Total	**362.46**	**410.53**	**430.74**	**416.34**	1620.07

परिशिष्ट-06 29

Naya Raipur Development Authority

In Front of Mahanadi Dwar of Mantralaya Raipur (C.G.)

Annual Work Plan For Year 2012-13
FOR THE 13TH FINANCE COMMISSION GRANTS FOR NAYA RAIPUR UNDER CAPITAL DEVELOPMENT

1- Eco-friendly Development Projects:

A. Use of Non-conventional energy resources:

(I) It is proposed to complete the establishment of 1.0 MW Solar Energy Plant at newly constructed State Secretariat Building to promote green energy concept in Naya Raipur. The work is already been given to CREDA, the nodal agency entrusted with development of renewal energy in the state. The cost of the project would be ₹ 10.50 crores including the O/M charges for ten years. The work is likely to be completed by December this year.

B. It is proposed to develop a Solar Energy Plant in the green belt of Naya Raipur to produce around 1.0 MW of Solar Power and to feed it in the electric grid. Approximately 5 acres of green belt area (in village Kuhera) in the master plan of Naya Raipur is being allotted for the purpose. The project will be implemented under PPP Model and to make the project economically / financially viable a **Viability Gap Funding** of ₹ 4.50 crores is estimated. The selection of Transaction Advisor for feasibility study, PPP structuring and for selection of a developer for implementation of Solar Power Projects of combined capacity of 5MW in Naya Raipur will be completed.

C. Conservation & Development of Water bodies:

(I) Development of RAKHI Lake:- The lake at the entry of Capital Complex in village Rakhi, is to be developed at an approximate cost of ₹ 25.00 crores. Around the lake, landscaping is also proposed to be done as a part of the project. The lake is to be enlarged and conserved. The approximate area of lake is 24.55 Ha. The detailed Project Report has been prepared and Administrative and Technical approval has been accorded accordingly. The work has been awarded and work is in progress, stipulated completion of the project is 12 months i.e. May,2013. it is likely to complete 100% earthwork, 75% of civil and landscaping work including the peripheral edge development of lake and hardscape part of development by the end of this year.

(II) It is proposed to conserve all the lakes presently in Naya Raipur area, however, out of these lakes the three major lakes namely the Sendh, Nawagoan and Khandwa lakes are to be developed and conserved in the first phase to maintain and improve the Urban Ecology of Naya Raipur. The area of these lakes are as under;

a. Sendh lake - 33.16 Ha.
b. Nawagoan lake - 65.08 Ha.
c. Khandwa lake - 45.84 Ha.

The Two lakes out three namely the Sendh and Nawagaon lakes are being developed under 13th Finance Commission Grant. The project cost for the conservation and development of these lakes is approximately ₹ 30.00 crores. The consultant for development and conservation of these lakes has already been appointed and stage-I estimate has been prepared. The concept plan has been finalized. This year the development and conservation of Nawagaon lake is being taken up and 70% of earth work, 25% hardscaping work will be completed.

C. Plantation and Development of City Park

(I) **Plantation around Lake-** Naya Raipur as per approved Master Plan will have 27% green area. It is proposed the plantation all around the lake as a part of landscape development and in the catchment under 13th Finance commission Grant. The approximate cost of which comes out to ₹ 5.0 crores. As per approved Master Plan 20 hectares of land has been selected in the catchment area of lakes for plantation and landscaping work this year with an approximate cost of Rs. 20 lakhs per hectare.

(II) **Development of Central City Park-** This central park comprises of the 2.2 km long median on a 200 m ROW road which is the ceremonial boulevard leading to the Capital Complex. It also includes the central rotary of 75m radius. The area of the City Park is around 28.63 Ha. The approximate cost of the development of City Park would be around ₹ 25.00 crores. Tenders for the work have been invited and award of contract is likely to be awarded by June this year. It is likely to complete 50% earth work and 25% hardscaping this year.

2- Buildings:

A. Housing for Government officers and employees

(I) Re-imbursement to C.G. Housing Board for Residential Houses being built by C.G. Housing Board

It was proposed to purchase 332 Residential Houses for Government employees from C.G. Housing Board at the cost of ₹ 42.20 crores. This amount is to be reimbursed to C.G. Housing Board. All the 332 residential units are almost completed and will be handed over to GAD Department this year. The details of residential houses are given below:-

Sl. No.	Types of Flats	Plinth area in Sq.M.	No. of Units	Unit cost in Lakhs	Estimated Cost in lakhs
1	G-Type Block				
	F 3A	107.52	36	24.83	893.88
	F 3B	101.48	48	24.34	1168.32
		Total	**84**		**2062.20**
2	H-Type Block				
	F 2A	69.79	36	14.60	525.60
		Total	**36**		**525.60**
3	I-Type Block				
		29.83	32	3.80	121.60
		45.72	108	7.98	861.84
		52.60	72	9.01	648.72
		Total	**212**		**1632.16**
		Grand Total	**332**		**4219.96**
				Or say	**4220.00**

(II) Construction of new Residential Houses- 316 units

316 new Residential Houses are to be constructed for the officers and employees of state Govt. in sector-17 and sector -18 at Naya Raipur. These Houses comprises of bungalows and flats as detailed below-

(a) In sector-18 it is proposed to construct 35 nos. of the "B"-type Bungalows/ Residential Houses for Honorable Ministers, Chief Secretary, Additional Chief Secretaries and Principal Secretary level officers and 35 nos. of "C"-type Bungalows/ Residential houses for Secretary level officers along with G+2 VIP Transit Hostel. The total cost for the same including site development would be ₹ 71.07 crores. The DPR will be prepared by PWD and work of construction will be started in the third quarter of this year.

(b) In sector-17 it is proposed to construct 18 nos. of the "D"-type and 36 nos. of "E"-type Residential Houses and 96 units of "F"-type Block, 48 units of "G"-type Block and 48 units of "H"-type Block for Government officials and employees. The total cost for the same including site development would be ₹ 86.73 crores. The work is likely to be awarded in June,2012 itself and it is likely to complete 80% of earth work and 25% of civil works and start of the site development work during this year.

Sl.no.	Type of Flats	No. of houses	Total cost of Construction (Rs. In Lacs)	Proposed Agency
1.	"D"	18	918.00	CGHB
2.	"E"	36	1649.00	CGHB
3.	"F"	96	2150.00	CGHB
4.	"G"	48	878.00	CGHB
5.	"H"	48	720.00	CGHB
6.	Site Development		2358.00	CGHB
Total		246	8673.00	

B. Office complex for State level Govt. offices

Apart from State Secretariat Building, a Head of Department Building is being constructed in Naya Raipur where 44 various Head of Departments offices were given office space. A few left Head of Departments offices are to be constructed in the office complex proposed in Naya Raipur. The area of office complex is approximately 50 Ha. The various office buildings proposed under 13th Finance Commission Grant are as detailed below-

Sl. No.	Name	Buildup area (in sq.m.)	Estimate cost (in crors.)	Approx Expenditure during year 2012-13
1.	PHQ	20800	45.00	12.00
2.	PWD	7500	16.50	2.00
3.	IRRIGATION	9500	21.00	4.50
4.	FOREST	17750	38.00	7.50
5.	Panchayat & Rural Development	7500	16.50	3.00
6.	Jail &Home Guard	4500	10.00	2.50
7.	SRD (Commercial Tax, Excise, Registration)	6000	13.50	3.50
8.	A composite building(for the various statutory bodies / Commission of the Government)	13500	30.00	2.00
9.	Paryavas Bhawan under Green Building concept (for HoDs under Housing & Environment Deptt.)	23000	35.00	5.50
10	Development of the infrastructure of the office complex.		24.50	13.00
Total			**250 Cr.**	**55.50**

For Works of WRD, Forest and PHQ the design and DPR have been finalized. The tenders for WRD & Forest have been invited and PHQ tender is being invited. These works are likely to be awarded in first quarter of this financial year. The DPRs of PWD, SRD, P&RD, Jail& Home Guard and Ayog Bhawan are being prepared by selected Architects in the consultation with concerned departments and the contract for these buildings are likely to be awarded during second quarter ending Sept.'2012. Fund flow of proposed works has been shown in above table

Total proposed expenditure as above in present financial year shall be approx Rs.55.50 crores and the work of the site development of the office complex will be started and 50% of earthwork and 20% of civil work will be completed this year.

Chief Executive Officer
Naya Raipur Development Authority
Raipur

Proposal for the 13th Finance Commission Grants(2011-2015) for Various Development in Naya

ANNEXURE-I

Amount in lakhs

Sl. No.	Name of work	Estimated Cost	Expenditure Flow				Total Expenditure (2011-15)	Remarks
			2011-12	2012-13	2013-14	2014-15		
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	**Eco-friendly Development Projects**							
	A. Use of Non-conventional Energy Resources							
	(a) VGF for Development of Solar Energy Park of 1 MW through PPP model	450.00	450.00				450.00	
	(b) Establishment of 1 MW solar Plant on the roof of State Secretariat Bldg.	1050.00	1050.00				1050.00	
	B. Conservation and Development of Water Bodies in NAYA RAIPUR							
	(a) Development of lake at Capitol Complex, Rakhi	2500.00	1480.00	520.00	500.00		2500.00	
	(b) Development of lakes at Sendh, Navagaon and Khandwa	3000.00	1000.00	1000.00	1000.00		3000.00	
	C. plantation and development 0f City park							
	(a) Plantation in lake catchment	500.00	200.00	200.00	100.00		500.00	
	(b) Development of Central City park	2500.00	800.00	1200.00	500.00		2500.00	
	TOTAL(A+B+C)	**10000.00**	**4980.00**	**2920.00**	**2100.00**	**0.00**	**10000.00**	
2	**Buildings**							
	A. Housing for Government employees							
	(a) Reimbursement to CG Housing Board for 332 Residential Houses built by them.	4220.00	4220.00	0.00	0.00	0.00	4220.00	
	(b.1)Construction of 246 Residential Houses (D type & below) by CGHB	8673.00	1800.00	3773.00	2200.00	900.00	8673.00	
	(b.2)Construction of 35 'B' type, 35 'C' Type and VIP Transit Hostel by PWD	7107.00	1550.00	3057.00	1800.00	700.00	7107.00	
	TOTAL(A)	**20000.00**	**7570.00**	**6830.00**	**4000.00**	**1600.00**	**20000.00**	
	B. Office Complex for State level Govt. offices	25000.00	1200.00	4000.00	7650.00	12150.00	25000.00	
	TOTAL(A+B)	**45000.00**	**8770.00**	**10830.00**	**11650.00**	**13750.00**	**45000.00**	
	GRAND TOTAL	**55000.00**	**13750.00**	**13750.00**	**13750.00**	**13750.00**	**55000.00**	

WORK PLAN OF 13th FINANCE COMMISSION GRANT TO POLICE DEPARTMENT FOR FINANCIAL YEAR 2012-13

(Amount in Rs. Lakh)

S.No.	District/Unit	Name of Work	Amount
		Year 2012-13	
		Training	
1	Police Academy, Chandkhuri	Swimming Pool	310.00
		Swimming Pool Building	100.00
		MT Garrage	90.00
		Main Entrance Gate	25.00
		Sub Total	**525.00**
2	CTJW College, Kanker	3 Nos. Hostel for Trainees (@175.00 Lackh each)	525.00
		Sub Total	**525.00**
		TOTAL	**1050.00**

Police Housing

		Residential Quarters for Non-Gazetted Officers			Residential Quarters for Constables/Head Constables			
		Nos.	Unit Cost (in Lakh)	Totai Cost (in Lakh)	Nos.	Unit Cost (in Lakh)	Total Cost (in Lakh)	
3	Durg	24	12.71	305.04	96	9.28	890.88	1195.92
	Kabirdham	12	12.71	152.52	48	9.28	445.44	597.96
	Surajpur	12	12.71	152.52	48	9.28	445.44	597.96
	Rajnandgaon	12	12.71	152.52	48	9.28	445.44	597.96
	Balrampur	12	12.71	152.52	48	9.28	445.44	597.96
	Bilaspur	12	12.71	152.52	72	9.28	668.16	820.68
	8th Bn. Rajnandgaon	12	12.71	152.52	48	9.28	445.44	597.96
	STF, Baghera- Durg	12	12.71	152.52	48	9.28	445.44	597.96
	4th Bn., Mana-Raipur				48	9.28	445.44	445.44
	Police Head Quarter, Raipur				22	9.28	204.16	204.16
	TOTAL	**108**		**1372.68**	**526**		**4881.28**	**6253.96**
	G.TOTAL							**7303.96**

Say Rs. 73.00 Crore

परिशिष्ट - 08

13 वें वित्त आयोग की योजना वर्ष 2012–13 के प्रावधानित राशि के कार्यों के लिए संशोधित कार्य योजना

13 वें वित्त आयोग की योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 हेतु राशि रूपये 37.50 करोड़ मात्र का प्रावधान स्वीकृत किया गया है । उक्त योजना के तहत 05 कार्य हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार हैं :–

क.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत प्रतिनग	प्रावधानित राशि
1	**मरम्मत एवं जीर्णोद्धार :–**		
	1. केन्द्रीय जेल दुर्ग में उन्नयन के फलस्वरूप विस्तारीकरण (बैरक, अस्पताल, सभा भवन आदि) के निर्माण कार्य	1106.86	
	2. केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर में सेक्टर वाल एवं पानी टंकी निर्माण	25.88	
	3. जिला जेल बैकुण्ठपुर में सशस्त्र बल हेतु बैरक निर्माण (किचन बाथरूम सहित) कार्य	26.00	
	4. जिला जेल राजनांदगांव में शासकीय आवास निर्माण कार्य	63.59	
	5. जिला जेल जांजगीर में विस्तारीकरण कार्य (मुख्य दीवार की लंबाई में वृद्धि, बैरक, गार्ड रूम निर्माण)	123.14	1994.00 लाख
	6. उप जेल सुकमा एवं नारायणपुर में सशस्त्र बल की कम्पनी को ठहराने हेतु 05–05 बैरक एवं संत्री पोस्ट का निर्माण कार्य	200.00	
	7. जिला जेल धमतरी में विस्तारीकरण कार्य एवं शासकीय आवास निर्माण	79.90	
	8. जिला जेल कांकेर में सशस्त्र बलों हेतु 02 बैरक निर्माण	27.00	
	9. उप जेल कटघोरा में शासकीय आवास निर्माण कार्य	132.63	
	10. उप जेल रामानुजगंज में सशस्त्र बलों हेतु 02 बैरक, मोर्चा, सीढी निर्माण एवं बंदियों हेतु 04 नग बैरक	71.00	
	11. उप जेल बीजापुर में 04 बैरक एवं चिकित्सालय निर्माण	118.00	
	12. केन्द्रीय जेल रायपुर में 20 केवी का सोलर लाईटिंग सिस्टम की स्थापना हेतु अंशदान	20.00 लाख	
	2. केन्द्रीय जेल बिलासपुर में 5 बैरेक्स (प्रति बैरक 20 बदी क्षमता वाली)	20.00 लाख प्रति बैरक 20.00 X 5	100.00 लाख
2	**शासकीय आवास निर्माण :–**		
	1. केन्द्रीय जेल दुर्ग में 01 नग ई–टाईप शासकीय आवास का निर्माण	13.00 लाख	13.00 लाख
	2. केन्द्रीय जेल बिलासपुर में 03 नग एफ–टाईप शासकीय आवास का निर्माण	8.00 लाख	24.00 लाख
	3. केन्द्रीय जेल दुर्ग में 06 नग एवं केन्द्रीय जेल बिलासपुर में 10 नग जी–टाईप शासकीय आवास निर्माण	5.00 लाख	80.00 लाख
	4. केन्द्रीय जेल दुर्ग में 16 नग एवं केन्द्रीय जेल बिलासपुर में 20 नग एच–टाईप शासकीय आवास निर्माण	3.50 लाख	126.00 लाख
	5. केन्द्रीय जेल दुर्ग में 01 नग आई–टाईप शासकीय आवास का निर्माण	2.50 लाख	2.50 लाख

नोट :– केन्द्रीय जेल रायपुर में हाई सिक्यूरिटी जोन (जेल) निर्माण कार्य के लिए वर्ष 2012–13 के मुख्य बजट में प्रावधान शामिल कर लिया गया है, अतः 13 वें वित्त आयोग में उक्त कार्य के स्थान पर उपरोक्त कार्य प्रस्तावित है ।

3	**सुरक्षा उपकरण :–** 1. प्रदेश की जेलों में सोलर सिक्यूरिटी सिस्टम की स्थापना 2. प्रदेश की नक्सल प्रभावित क्षेत्र की 10 जेलों हेतु कंसर्टीना वायर फैंसिंग कार्य 3. प्रदेश की नक्सल प्रभावित क्षेत्र की 10 जेलों हेतु फायर फायटिंग उपकरण क्रय	रू. 150/– मात्र प्रति रनिंग मीटर 45.00 लाख के.जे. हेतु 15.00 लाख 5.00 लाख	293.00 लाख 45.00 लाख 135.00 लाख 50.00 लाख
4	**नक्सल प्रभावित क्षेत्र की जेलों हेतु विशेष व्यवस्था :–** 1. केन्द्रीय जेल बिलासपुर के जेल परिसर में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य 2. प्रदेश की नक्सल प्रभावित क्षेत्र जेलों (केन्द्रीय जेल जगदलपुर, जिला जेल कांकेर, महासमुन्द तथा धमतरी) बाह्य सुरक्षा हेतु तैनात बलों के रहने हेतु 02–02 बैरक (20–20 की क्षमता वाली) तथा 02–02 संत्री पोस्ट का निर्माण कार्य	20.00 लाख 117.50 लाख	137.50 लाख
5	**नवीन जिला जेल दन्तेवाड़ा का निर्माण कार्य** 20 बंदी क्षमता वाली 10 बैरक का निर्माण, प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवास का निर्माण 2 एफ टाईप (12 लाख प्रति), 10 जी टाईप (10 लाख प्रति), 40 एच टाईप (8 लाख प्रति), एवं 02 नग आई टाईप (5 लाख प्रति)	20.00 लाख प्रति बैरक 20.00 X 10 75.00 लाख 24.00 लाख 100.00 लाख 320.00 लाख 10.00 लाख	200.00 लाख 75.00 लाख 24.00 लाख 100.00 लाख 320.00 लाख 10.00 लाख
	केन्द्रीय जेल बिलासपुर हेतु 11 एवं नवीन जिला जेल दन्तेवाड़ा हेतु 10 प्रस्तावित बैरकों हेतु प्रति बैरक 4 शौचालय एवं 04 स्नानागार के मान से कुल 84 नग शौचालय एवं 84 स्नानागार	04 शौचालय एवं 04 स्नानागार हेतु रूपये 1.00 लाख के मान से कुल 84 शौचा. एवं 84 स्ना.हेतु	21.00 लाख
		योग	**3750.00**

13 वें वित्त आयोग की योजना वर्ष 2012–13 के उपरोक्त 05 कार्यों के लिए कुल रूपये 37.50 करोड़ के कार्य कराया जाना है ।

1. मरम्मत एवं जीर्णोद्धार :–

अ. जेलों की सुरक्षा/जेल व्यवस्था हेतु विभिन्न का निर्माण कार्य :–

राज्य शासन द्वारा केन्द्रीय जेल रायपुर में हाई सिक्यूरिटी जोन (जेल) निर्माण कार्य का प्रावधान मुख्य बजट में प्रावधान किया गया है अतः अब 13 वें वित्त आयोग की योजना वर्ष

2012–13 में इस कार्य की आवश्यकता नहीं है । उक्त कार्य के स्थान पर अन्य अतिमहत्वपूर्ण कार्य जैसे :– केन्द्रीय जेल दुर्ग का उन्नयन विस्तारीकरण, केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर में निर्मित बैरकों के लिए सेक्टर वाल एवं पानी टंकी का निर्माण, जिला जेल बैकुण्ठपुर/कांकेर/उप जेल रामानुजगंज में सशस्त्र बल के लिए बैरक निर्माण, जिला जेल जांजगीर का विस्तारीकरण, जिला जेल राजनांदगांव एवं उप जेल कटघोरा में कर्मचारियों हेतु शासकीय आवास निर्माण एवं उप जेल बीजापुर में बैरक एवं चिकित्सालय का निर्माण कार्य । उक्त कार्यों के लिए कुल रूपये 1994.00 लाख का व्यय अनुमानित है । उक्त कार्य कराये जाने हेतु स्वीकृति दी जाना प्रस्तावित है ।

ब. केन्द्रीय जेल बिलासपुर में 11 बैरेक्स का निर्माण :–

प्रदेश में वर्तमान में संचालित 25 जेलों की अधिकृत आवास क्षमता कुल 5430 बंदी की है जिसके विरूद्ध माह **मार्च 2012** की स्थिति में कुल 13816 पुरूष/महिला बंदी निरूद्ध हैं । केन्द्रीय जेल बिलासपुर की अधिकृत आवास क्षमता 628 (558 पुरूष+70 महिला) के विरूद्ध माह मार्च 2012 में 2311 पुरूष/महिला बंदी निरूद्ध थे इससे स्पष्ट है कि केन्द्रीय जेल बिलासपुर में ओव्हर क्राउडिंग की समस्या ज्यादा है केन्द्रीय जेल बिलासपुर में उक्त समस्या के निराकरण के लिए 5 नग अतिरिक्त बैरेक्स का निर्माण कराया जाना है जिस पर 20.00 लाख प्रतिबैरक के मान से 5 बैरकों के लिए कुल रूपये 100.00 लाख का प्रावधान किया जाना है तथा कार्य की स्वीकृति दी जाना प्रस्तावित है ।

2. शासकीय आवास निर्माण :–

प्रदेश की केन्द्रीय जेल दुर्ग एवं केन्द्रीय जेल बिलासपुर में कार्यरत स्टाफ के लिए स्टाफ क्वार्टर का निर्माण अतिआवश्यक है क्योंकि जेल नियमावली में स्पष्ट प्रावधान है कि जेल कर्मियों को जेल परिसर में ही निवास कराया जाये ताकि वे आपात स्थिति में तत्काल कार्य स्थल पर उपस्थित हो सके । प्रदेश की केन्द्रीय जेल दुर्ग में 01 नग ई, 06 नग जी, 16 नग एच एवं 01 नग आई टाईप तथा केन्द्रीय जेल बिलासपुर में कार्यरत स्टाफ के लिए 03 नग एफ, 10 नग जी एवं 20 नग एच टाईप आवास के निर्माण कराये जाने हैं । इस हेतु कुल रूपये 245.50 लाख का प्रावधान किया गया है । उक्त कार्य कराये जाने हेतु स्वीकृति दी जाना प्रस्तावित है ।

3. सुरक्षा उपकरण :–

प्रदेश में नक्सली गतिविधियॉ बढ़ गई हैं जिस कारण जेलों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए आधुनिक उपकरण क्रय किये जाने होंगें, साथ ही जेलों में क्रेडा के सहयोग से सोलर सिक्यूरिटी सिस्टम की स्थापना कराया जाना होगा । जेलों की सुरक्षा के संबंध में निम्नानुसार कार्य कराये जाने प्रस्तावित है :–

1. प्रदेश की जेलों में सोलर सिक्यूरिटी सिस्टम की स्थापना
2. प्रदेश की नक्सल प्रभावित क्षेत्र की 10 जेलों हेतु कंसर्टीना वायर फैंसिंग कार्य
2. प्रदेश की नक्सल प्रभावित क्षेत्र की 10 जेलों हेतु फायर फायटिंग उपकरण क्रय

उपरोक्त सुरक्षा उपकरण क्रय के लिए कुल रूपये 523.00 लाख का प्रावधान किया जा चुका है । उक्त कार्य कराये जाने हेतु स्वीकृति दी जाना प्रस्तावित है ।

4. नक्सल प्रभावित क्षेत्र की जेलों हेतु विशेष व्यवस्था :–

प्रदेश में वर्तमान में संचालित 25 जेलें संचालित हैं जिनमें से 16 जेल नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थित होने के कारण अत्यधिक संवेदनशील हैं । केन्द्रीय जेल जगदलपुर, जिला जेल कांकेर, धमतरी तथा महासमुन्द जेल के बाह्य सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात बलों को ठहराने हेतु 20–20 की क्षमता वाले 02–02 बैरक (किचन, शौचालय, स्नानागार सहित) तथा 02–02 संत्री पोस्ट का निर्माण कराया जाना है । उक्त कार्य पर कुल रू. 117.50 लाख मात्र का व्यय संभावित है ।

केन्द्रीय जेल बिलासपुर में कर्मचारी आवास के हिस्से में कोई बाउण्ड्रीवाल वर्तमान में नहीं है जिस कारण जेल परिसर में बाहरी व्यक्ति भी आसानी से प्रवेश कर जाते हैं अतः केन्द्रीय जेल बिलासपुर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बाउण्ड्रीवाल का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है । इस कार्य पर कुल 20.00 लाख मात्र का व्यय अनुमानित है ।

अतः जेलों में सुरक्षा बलों के लिए बैरक तथा संत्री पोस्ट निर्माण एवं केन्द्रीय जेल बिलासपुर में बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु कुल रू. 137.50 करोड़ का प्रावधान कराया जाना प्रस्तावित है ।

5. नवीन जिला जेल दन्तेवाड़ा का निर्माण कार्य

प्रदेश में पूर्व में उप जेल के रूप में दन्तेवाड़ा जिले में 01 जेल संचालित थी शासन आदेशानुसार उप जेल दन्तेवाड़ा का उन्नयन किया जाकर जिला जेल का दर्जा दिया गया था । जिला जेल के मान से उप जेल दन्तेवाड़ा में बंदियों को रखने की क्षमता नहीं थी । केन्द्र सरकार की जेल आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2002–2007 के तहत दन्तेवाड़ा में संचालित जेल में 50–50 बंदी क्षमता वाली 02 बैरक निर्मित कराई गई है वर्तमान में जिला जेल दन्तेवाड़ा को अधिकृत बंदी आवास क्षमता 150 बंदी की है जिसके विरूद्ध लगभग 700 बंदी निरूद्ध हैं जिनमें अधिकांश नक्सली बंदी है । जिला जेल दन्तेवाड़ा घोर नक्सल क्षेत्र में स्थित एक अतिसंवेदनशील जेल हैं । जिला जेल दन्तेवाड़ा में निरूद्ध नक्सली बंदियों द्वारा वर्ष 2007 में एक बार जेल ब्रेक की घटना को अंजाम दिया जा चुका है । जिला दन्तेवाड़ा में आए दिन नक्सलियों द्वारा गंभीर किस्म की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है ।

अधीक्षक, जिला जेल दन्तेवाड़ा द्वारा जेल की वर्तमान स्थिति को सुरक्षा के दृष्टिगत मजबूत नहीं बताया गया अतः जिला जेल दन्तेवाड़ा को किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाना सुरक्षा की दृष्टि से उचित होगा । नवीन जिला जेल निर्माण के लिए जेल अधीक्षक, जिला दण्डाधिकारी, पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा जा चुंका है । भूमि चयन की प्रक्रिया जारी है ।

नवीन जिला जेल में 20 बंदी क्षमता वाली 10 बैरक का निर्माण, प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य, अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवास का निर्माण की आवश्यकता होगी जिसके लिए राशि रूपये 750.00 लाख के व्यय का प्रावधान किया जा चुका है । उक्त कार्य कराये जाने हेतु स्वीकृति दी जाना प्रस्तावित है ।

6. अतिरिक्त बैरकों हेतु शौचालय एवं स्नानागार का निर्माण

केन्द्रीय जेल बिलासपुर में प्रस्तावित 11 अतिरिक्त बैरक (प्रति बैरक 20 बंदी क्षमता) एवं नवीन जिला जेल दन्तेवाड़ा के लिए प्रस्तावित 10 नग बैरकों (प्रति बैरक 20 बंदी क्षमता) के लिए प्रति बैरक 04 शौचालय एवं 04 स्नानागार इस प्रकार कुल 84 नग शौचालय एवं 84 नग

स्नानागार हेतु कुल रूपये 21.00 लाख के व्यय का प्रावधान हो चुका है । उक्त कार्य कराये जाने हेतु स्वीकृति दी जाना प्रस्तावित है ।

नक्सल प्रभावित क्षेत्र की जेलों की सूची

1. केन्द्रीय जेल जगदलपुर
2. जिला जेल दन्तेवाड़ा
3. जिला जेल कांकेर
4. केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर
5. जिला जेल बैकुण्ठपुर
6. जिला जेल जशपुर
7. उप जेल सूरजपुर
8. उप जेल रामानुजगंज
9. जिला जेल कोरबा
10. उप जेल डोंगरगढ़
11. जिला जेल राजनांदगांव
12. जिला जेल धमतरी
13. उप जेल गरियाबन्द
14. उप जेल संजरीबालोद
15. उप जेल सुकमा (बंद)
16. उप जेल नारायणपुर (बंद)

Directorate of Culture and Archaeology
Govt. of Chhattisgarh

ABSTRACT

Proposal for XIIIth Finance Commission
Scheme for Preservation of Heritage
Year 2012-13

S. NO.	PARTICULARS	Prop. Amount In Lac Rs.
I	CONSERVATION WORK OF MONUMENTS	665.00
II	CHEMICAL CONSERVATION OF MONUMENTS & ANTIQUITIES	25.00
III	ARCHAEOLOGICAL MUSEUM	350.00
IV	SURVEY & EXPLORATION	10.00
V	WORKSHOP/SEMINAR ON CONSERVATION AND PRESERVATION OF HERITAGE.	30.00
VI	TRAINING FOR HERITAGE PRESERVATION	8.00
VII	EQUIPMENTS	8.00
VIII	HONORARIUM	4.00
IX	DOCUMENTATION, PUBLICATION & EXHIBITION	25.00
	Grand Total	**1125.00**

Proposal for XIII[th] Finance Commission
Scheme for Preservation of Heritage
Year 2012-13

I. CONSERVATION WORK OF MONUMENTS

(REVISED)

S. No.	Monuments / Sites	Place, District	Prop. Amount in Lacs Rs.
1	Kuleshwar Temple (Stage-II & Final Stage)	Rajim, Raipur	80.00
2	Siddheshwar Temple	Palari, Balodabazar	90.00
3	Swastik Vihar	Sirpur, Mahasamund	05.00
4	Chherki Mahal	Chaura, (Bhoramdeo) Kabirdham	50.00
5	Madawa Mahal	Chaura, (Bhoramdeo) Kabirdham	40.00
6	Shiv Temple	Chhindgaon, Bastar	120.00
7	Satmahala Temple Groups	Kalcha Bhadwahi, Sarguja	80.00
8	Excavated Archaeological Site	Madkudip, Bilaspur	10.00
9	Excavated Archaeological Site	Maheshpur, Sarguja	110.00
10	Excavated Archaeological Site	Silli Pachrahi, Kabirdham	80.00
Total			**665.00**

Proposal for XIII[th] Finance Commission
Scheme for Preservation of Heritage
Year 2012-13

II. CHEMICAL CONSERVATION OF MONUMENTS & ANTIQUITIES

S. No.	Monuments & Antiquities	Place, District	Prop. Amount In Lac Rs.
1	Shiv Temple	Kirarigodhi, Bilaspur	4.00
2	Shiv Temple	Nagpura, Durg	4.00
3	Shiv Temple	Gumadapal, Bastar	3.00
4	Devrani-Jethani Temple & Sculptures	Amerikapa, Bilaspur	14.00
Total			**25.00**

Proposal for XIII[th] Finance Commission
Scheme for Preservation of Heritage
Year 2012-13

III. ARCHAEOLOGICAL MUSEUM

S. No.	Particulars	Prop. Amount In Lac Rs.
01	• Renovation and upgradation museums say, Purchase of Equipment for Museum Maintenance, Preservation of Antiquities, Display work, Security equipments, Storage etc.	
	1. Mahant Ghasidas Memorial Museum, Raipur	50.00
	2. Archaeological Museum, Sirpur, Mahasamund	200.00
	3. District Archaeological Museum, Bilaspur	100.00
Total		**350.00**

Proposal for XIII[th] Finance Commission
Scheme for Preservation of Heritage
Year 2012-13

IV. SURVEY & EXPLORATION

S. No.	Particulars	Prop. Amount In Lac Rs.
01	• River Valley Survey (Origin to confluence in Chhattisgarh) • Special Area, Thematic Survey. • Village to village survey of Chhattisgarh (Bastar, Kanker, Bilaspur, Sarguja, Koria, Kabirdham etc.)	10.00
	Total	**10.00**

Proposal for XIIIth Finance Commission
Scheme for Preservation of Heritage
Year 2012-13

V. WORKSHOP/SEMINAR ON CONSERVATION AND PRESERVATION OF HERITAGE.

S. No.	Particulars	Prop. Amount In Lac Rs.
01	1) International Seminar / Workshop on Archaeology & Heritage. 2) National and State Level Seminar / Workshop on Archaeology & Heritage. 3) Presentation and Shows Based on the Heritage of Chhattisgarh.	30.00
Total		**30.00**

PROPOSAL FOR XIII[TH] FINANCE COMMISSION
SCHEME FOR PRESERVATION OF HERITAGE
YEAR 2012-13

VI. TRAINING FOR HERITAGE

S. No.	Particulars	Prop. Amount In Lac Rs.
01	• Training of Tourist Guides. • Training of Practical aspects of Museum methods. • Field Training of ancient sites for students / amateurs.	8.00
Total		8.00

PROPOSAL FOR XIII[TH] FINANCE COMMISSION
SCHEME FOR PRESERVATION OF HERITAGE
YEAR 2012-13

VII. EQUIPMENT

S. No.	Particulars	Prop. Amount in Lac Rs.
01	• Equipments for Conservation, Preservation, Photography Laboratory i.e. - Furniture, Scientific Equipments, Computer, Scanner, Photocopy Machine etc. • Vehicle hire/fuel charges etc.	8.00
Total		**8.00**

PROPOSAL FOR XIII[TH] FINANCE COMMISSION
SCHEME FOR PRESERVATION OF HERITAGE
YEAR 2012-13

VIII. HONORARIUM

S. No.	Particulars	Prop. Amount In Lac Rs.
01	For Different Subjects and Technical Expert's Honorarium	4.00
Total		**4.00**

PROPOSAL FOR XIIITH FINANCE COMMISSION
SCHEME FOR PRESERVATION OF HERITAGE
YEAR 2012-13

IX. DOCUMENTATION, PUBLICATION & EXHIBITION

S. No.	Particulars	Prop. Amount In Lac Rs.
01	Publication & Documentation of Heritage Brochure, Guide Books of Monuments & Museums, Previous Excavation and Survey Reports etc. and Exhibition Based on Heritage.	25.00
Total		**25.00**

परिशिष्ट-10

Proposal for 13th Finance Commission year 2012-2013

No.	District	No. of Sanctioned AWCs	No. of Sanctioned AWC Buildings	No. of AWCs for which Building is not sanctioned	Proposal for 13th Finance Commission year 2012-2013				Amount in (lakhas)
					Ganral	T.S.P	S.C.P	Total	
1	Bastar	1849	1007	842	24	31	0	55	247.50
2	Kondagaon	1445	869	576	16	21	0	37	166.50
3	Dhamtari	1007	961	46	1	1	0	2	9.00
4	Raigarh	2680	1899	781	24	17	4	45	202.50
5	Janjgeer	1979	1751	228	10	0	12	22	99.00
6	Kabirdham	1578	1275	303	9	0	0	9	40.50
7	Korea	1357	990	367	12	13	0	25	112.50
8	Sarguja	1747	1108	639	21	27	0	48	216.00
9	Surajpur	1760	1035	725	23	31	0	54	243.00
10	Balrampur	1647	1152	495	16	21	0	37	166.50
11	Durg	1461	815	646	18	0	0	18	81.00
12	Balod	1409	957	452	12	5	0	17	76.50
13	Bemetara	1029	758	271	8	0	2	10	45.00
14	Kanker	1870	1402	468	15	22	0	37	166.50
15	Rajnandgaon	2463	1657	806	21	4	0	25	112.50
16	Dantewada	993	644	349	10	15	0	25	112.50
17	Sukma	915	490	425	13	18	0	31	139.50
18	Narayanpur	372	241	131	4	6	0	10	45.00
19	Mahasamund	1530	1395	135	5	0	1	6	27.00
20	Jashpur	2946	2397	549	20	28	0	48	216.00
21	Bijapur	1108	539	569	16	22	0	38	171.00

Proposal for 13th Finance Commission year 2012-2013

No	District	No. of Sanctioned AWCs	No. of Sanctioned AWC Buildings	No. of AWCs for which Building is not sanctioned	Proposal for 13th Finance Commission year 2012-2013				Amount in (lakhas)
					Ganral	T.S.P	S.C.P	Total	
22	Bilaspur	2667	1531	1136	34	8	24	66	297.00
23	Mungeli	1014	550	464	14	0	25	39	175.50
24	Raipur	1828	1051	777	25	0	5	30	135.00
25	Balodabazar	1677	1146	531	17	0	27	44	198.00
26	Gariyaband	1167	812	355	12	5	0	17	76.50
27	Korba	2265	1647	618	17	21	0	38	171.00
	Total	**43763**	**30079**	**13684**	**417**	**316**	**100**	**833**	**3748.50**

jont Director
Women & Child Development
Raipur (C.G)

द्वितीय चरण वर्ष 2012-13 में प्रस्तावित कार्य :—

1. आवासीय क्वार्टर -	
एच-टाईप 01 - 8 यूनिट	- रूपये 78,64,000
जी-टाईप -10 यूनिट	- रूपये 1,11,28,000
एफ-टाईप 01 - 5 यूनिट	- रूपये 1,16,38,000
आई-टाईप 06 नग	- रूपये 22,50,000
2. वाहन शेड निर्माण	- रूपये 8,48,000
3. ड्रेन एण्ड रोड आवासीय भवन तक	- रूपये 1,50,00,000
4. मुख्य भवन एवं आवासीय भवन के मध्य बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य	- रूपये 1,13,20,000
5. छात्रावास किचन का विस्तार	- रूपये 10,00,000
6. नरेगा एवं स्कूल के बच्चों, विद्यार्थियों के सहयोग से में लैण्ड स्केपिंग एवं वृक्षारोपण कार्य	- रूपये 89,52,000
7. फर्नीचर व्यवस्था	
कुल योग	**- रूपये 7,00,00,000**

तृतीय चरण वर्ष 2013-14 में प्रस्तावित कार्य

1. लोक निर्माण विभाग द्वारा आवासीय क्वार्टर हेतु	
सी-टाईप 02 ब्लाक-02 यूनिट	- रूपये 1,40,43,000
डी-टाईप 02 ब्लाक-02 यूनिट	- रूपये 82,49,000
ई-टाईप 01 ब्लाक-04 यूनिट	- रूपये 1,40,43,000
2. स्ट्रीट लाईट व्यवस्था एवं वातानुकूलित मशीनों की व्यवस्था	- रूपये 1,00,00,000
3. विभिन्न पहुंच मार्गो का निर्माण	- रूपये 1,36,65,000
4. फर्नीचर व्यवस्था	- रूपये 1,00,00,000
कुल योग	**- रूपये 7,00,00,000**

चतुर्थ चरण वर्ष 2014-15 में प्रस्तावित कार्य

1. लोक निर्माण विभाग द्वारा आवासीय क्वार्टर हेतु बी-टाईप 02 ब्लाक-02 यूनिट	- रूपये 2,00,00,000
2. वृक्षारोपण रखरखाव	- रूपये 50,00,000
3. सेटेलाईट बिल्डिग कार्य	- रूपये 1,00,00,000

FOREST DEPARTMENT
13TH FINANCE COMMISSION
WORK PLAN FOR 2012-13

1. Forests & Wild life

Chhattisgarh has a total forest area of 59772 Sq. Km, which is 44.2% of the total Geographical area of the State. The State has the 3rd largest forest cover in the country. Due to ever increasing biotic pressure, 30% of the forests are in degraded state. Bamboo forests are spread over 11000 Sq Km., of which 50% are degraded and unproductive.

There are 2 National Parks, 8 Sanctuaries, 3 Tiger Reserve & 1 Biosphere Reserve constituted for protection and development of wild life. The area covered under these Protected Areas is about 15% of the total forest area of the state. Indrawati National Park, Sitanadi - Udanti and Achanakmar Sanctuaries have been included in the Project Tiger.

2. Forest and forest dwellers

Of the 19744 villages in the State, 11185 villages are situated within the 5 km. periphery of the forests. Forest dwellers are mostly tribals, whose population is 32% of the total population of the state. Areas within and in the vicinity of forests are mostly underdeveloped, because of their geographically disadvantageous location. Their economy is mostly dependant on forests. Forests provide about 650 lakh man-days of employment directly to people in the most remote areas of the State.

Forest generates about Rs. 350 crore as revenue annually from the sale of timber and bamboos. Forests are very rich in Minor Forest Produces. Forest dwellers earn about ₹ 580 crore through employments generated from the collection and sale of minor forest produces. As per the Govt. policy, people are allowed to collect fallen fuel wood free of cost, for their domestic use. About Rs. 300 crore worth of fuel wood is collected by people from forest annually. People get about Rs. 200 crore worth of grasses and fodder from forests as per facilities provided under the grazing rules. As per the Nistar Policy, people living within 5 kms of the boundary of the forests are provided poles, bamboos and fuel wood at concessional rates. Basods and Pan Bareza families are provided royalty free bamboos from depots. Concessions provided under Nistar Policy annually are worth Rs. 50 crore. Thus, the total direct contribution of forest towards the economy of forest dwellers is Rs. 1430 crores. This itself signifies the importance of forests in the state economy.

3. Forest Management

Forests are managed as per the provisions of working plans approved by GOI. There are 11000 officers & Staff engaged in protection and management of forests. As per the forest policy of the state, co-operation of people is being taken for protection, development and management of forests. So far 7887 Joint Forest Management committees have been formed in the state.

4. Departmental Budget and additional financial requirement

Budgetary provision in the state plan for forestry sector during 2012-13 is Rs. 434 crores which includes Rs. 102.78 crores as 13th Finance Commission Grant also. Despite the fact that the State is having 44% of forest area, the budget allocation to the forestry sector in the state plan is about 2-2.5%, which is not enough, to carry out all the forestry operations prescribed in the working plan and to undertake developmental and other works. In light of the vast forest area, requirement for forest management, forest development and dependence of people on forests for livelihood, additional financial provisions in the forestry sector are needed.

Proposal Under 13th finance commission for year 2012-13

It is proposed to give priority to works, which are important for the protection & development of forests, but for which, sufficient budgetary provisions under the State Plan, CSP and CSS are not available. As per the guidelines by MOEF, the emphasis has also been given to the works related with economic development of people in and around the forest areas especially in the areas affected by the activities of Left Wing Extremists (LWE). The following schemes have been proposed: -

(1) Installation of generators at important offices :

Disruption in electric power supply in the left wing extremists affected areas and other remote areas has become a regular phenomena It not only hampers the official works but also effect the flow of information to higher offices. Rs. 200 lakhs are proposed for installation of generators in DFO/SDO/Range officer office. It is proposed to provide generators for research nurseries and FMIS division.

(2) Community organization and capacity building:

Community organization and capacity building among the local people in forest areas is going to be an important work. The existing local institution such as JFMCs, SHGs and PRIs are to be strengthened by suitable capacity building programmes and new institution will also to be created. Good NGOs will also be engaged for assisting the forestry administration and local people in community organization, capacity building and marketing of local products. Rs. 70 lakhs are proposed to be incurred for this purpose in the year 2012-13.

(3) Improving rural infrastructure in Forest Villages -

Irrigation facilities, electricity and roads are an important component of rural infrastructure. Improving irrigation potential not only helps in enhancing the local agriculture productivity but, at the same time, improves the under ground water table. Thus, for improving rural infrastructure, creation of water bodies for irrigation and other purposes and installation of solar light at suitable forest villages construction of approach road, culverts, school building, drinking water facilities and development of agriculture etc are being included in the project. Rs. 900 lakhs are proposed for improving rural infrastructure of forest village in the year 2012-13.

(4) Implementing poverty alleviation and income generating activities -

To generate employment potential and income for the local people, collection, processing and marketing of the product based on different forest produce are proposed to be carried out in organized manner in LWE affected areas. At village level, different processing units will be started taking different forest produce as the raw material such as Bamboo, Lac, Mahul leaves, Oil seed, etc. These processing centres/ units will be managed by the local institution such as SHGs, JFMCs, etc. Rs. 50 lakhs are proposed for this purpose in the year 2012-13.

(5) Upgradation and Maintenance of Forest Roads

The state has 13486 km of forest roads, which are crucial for the transportation of forest produce and for communication of the people living in remote forest areas. Forest roads are fair weather roads, which are cut off during rainy seasons, because of rivers and small nalas. In remote areas these forest roads are the only means of communication to rural people. It is necessary to upgrade them to facilitate communication especially in rainy season. It is proposed to upgrade 150 km forest road into WBM road. Under 12th/13th Finance Commission and Departmental budget a total of about 650 km forest road were upgraded into WBM roads. These WBM roads are not properly maintained due to paucity of funds. It is proposed to repair and maintain these roads in the year 2012-13. An amount of Rs. 2100 lakh is proposed for this work.

(6) Rehabilitation & Regeneration of Degraded and Bamboo Forests in Orange Area

There is a large chunk of degraded forest in orange areas. Many of these areas are not covered under the working plans. Orange area contains degraded Bamboo Forest also. To rehabilitate and regenerate these areas Cut back operation, Cleaning and earth work of bamboo clumps and plantation activities has been proposal in financial year 2012-13 to treat and plant an approximate area of 700 ha. at the cost of Rs. 1500 lakhs.

(7) Upgradation of Nurseries

Nurseries are most important for success of any plantation. Due to paucity of funds, the plants are raised in the traditional manner without any modern input. So the nurseries should be fully equipped with modern techniques to produce high quality planting material. Mist and hardening chamber and sprinkler irrigation system for judicious use of water will be established. The nursery staff will be properly trained to handle modern equipments. A part of the plants will be raised in root trainer. It is proposed to partially modernize and develop 20 nurseries at a cost of Rs. 500 lakhs to produce good quality planting material in year 2012-13. Part of this infrastructure development will be taken up in the year 2013-14.

(8) **Non-conventional energy resources and Rain water harvesting**

Most of the Forest Rest houses, Residential Quarters of Forest staff and Forest Check posts are located in the interior and remote areas where providing electricity connection is not at all possible. So staffs are still living in darkness, the only source of lighting in such places is lantern. Because of remoteness and distance from villages it is not possible to provide electric connection to each and every staff quarter. So to harness the naturally available abundant solar energy and popularize and promote the non-convention energy resources, it is proposed to install solar lighting system, water heating system in forest rest houses and solar lighting system, solar lantern to staff quarters and check posts. The department will also try to avail the Govt. subsidy to reduce the cost of installation.

The Ground water table is decreasing every year due to vagaries of monsoon, indiscriminate exploitation of ground water etc. The Government is making all efforts to construct and popularize Rain water harvesting system in all government buildings. The Forest department is not able to implement the same due lack of funds. So to harvest the rain water and to conserve the available water it is proposed to construct Rain water harvesting system in the forest department buildings where ever possible. If it is implemented the forest department will become a role model for other departments. To achieve the above objectives 125 lakhs is proposed.

(9) **Improvement of Basic Amenities in Forest Colonies**

Forest staff has to live in very remote area to manage and protect the valuable natural resource i.e. forests. Their residences are normally located away from residential areas of the village having no electricity boundary walls and drinking water facilities. Even some of the forest colonies located in the district and forest division headquarter also lack in proper basic amenities. It is proposed to provide basic facilities like providing safe drinking water, boundary walls and electricity connection to individual house hold and other miscellaneous works under this scheme. The proposed amount is 250 lakhs for the year 2012-13.

(10) **Construction and strengthening of Forest Barriers**

There are 365 forest barriers in the State out of which 35 are inter State barriers. Almost all barriers do not have proper building. In check posts the staffs are supposed to do round the clock duty but because of non availability of proper building and basic facilities like latrine, bathroom, lighting and drinking water, staff are forced to live in nearby villages which affect the forest protection works. So it is proposed to construct forest barriers and building of staff at inter state and highly sensitive location at a cost of 200 lakhs.

(11) Wildlife Habitat Development outside Protected Area

There are 2 National Park, 3 Tiger Reserve and 11 Sanctuaries in the State. Wildlife habitat development & other infrastructure development in these protected areas are being taken up by on going plan schemes of State Govt. and centrally sponsored schemes of Govt. of India. However there is no separate scheme for wildlife habitat development and biodiversity conservation outside the protected area, whereas these area occupy abundant wildlife and rich biodiversity. Every year in the summer season scarcity of water in these areas causes great misery to wildlife. The poacher also takes the benefit of this. To ease this problem it is proposed to create water bodies in all 32 division areas to provide water to wildlife during summer and other season. About 1000 lakhs is proposed for the above works.

(12) Entry Point Activity in JFM Committees

There are JFM 7887 JFM committees in the state. Of these only 2000 committees are getting sizable amount of funds in lieu of protection or harvesting of coupes in the area's of concerned JFM committees. However more then 4000 committees do not have sufficient funds to carry out various development activities. It is proposed to carryout entry point activities in these JFM committees under 13th finance commission. For the year 2012-13 Rs. 750 lakh has been proposed for entry point activities.

(13) Infrastructure Development works in sale depots

There are 28 timber and Bamboo depots in the state. At present, about 1.80 lakh Cmt. of timber and 50,000 notional ton of Bamboo are being disposed annually from these depots which fetch revenue to the tune of Rs. 350 crore per annum. Most of these depots were established about 30 years back and not being maintained properly because of paucity of funds. The general condition of infrastructure facilities and services created at that time have deteriorated with passage of time. Moreover, many of these depot are located in Naxal infested areas of the state and hence the security of dumped forest produce in such depot is of great concern and hence following works have been proposed to upgrade the facilities and services in such depot under 13th finance commission grants,

(i) Construction / Maintenance of Fencing.
(ii) Construction and strengthening of internal roads
(iii) Construction of Auction Hall, EMD room
(iv) Internal Electrification
(v) Water Supply and fire protection

For above works an amount of Rs. 600 lakhs is proposed for the year 2012-13.

(14) Training and Development of training infrastructure

There is a strong need for refresher courses and training to staff paricularly forest guard, forester and deputy rangers. Though IFS officers are covered under the refresher courses of MOEF schemes but state officers like Assistant Conservator of Forests and Range officers also require such refresher courses and trainings. There are 3 training school in the state which also need to be revamped in the training facilities. So to cater the needs of training and development of infrastructure facilities at training schools. An amount of Rs. 250 lakh is proposed to be spent during the year 2012-13.

(15) Infrastructure Development in New Divisional Head Quarter

Chhattisgarh Government has created 9 new districts. As a result 5 new forest division offices, SDO office, other buildings and related infrastructure has to be established. A provision of Rs. 200 lakh is being proposed for infrastructure development for new Forest Divisions office and Quarters for staff for the year 2012-13.

(16) Environmental Education to School/College Students

To create awareness and to sensitize school/college student towards environment, forests and wildlife protection and their conservation, it is proposed to conduct excursion cum camping programme in forest areas for 2000 school and college student. The basic infrastructure for camping of these students at camping sites will be created in a phased manner. For this a provision of Rs. 200 lakh is proposed in the year 2012-13 under the 13th Finance commission grant.

(17) Eco-Tourism Development outside Protected Areas through local JFMC

In Chhatisgarh there are number of Eco-tourism spots outside protected areas like Satrenga, Buka, Futka Pahad, Chaturgarh, Mainpat, Kailash caves, Tirathgarh fall etc. Eco-tourism can provide gainful employment to local JFMC member through out the year. These spots lack basic amenities to attract tourists. For Eco-tourism Development outside protected areas basic infrastructure facilities like tourist huts, motor boats, lodging facilities, tracking routes etc are to be created. These eco-tourism centers will be run by local Joint Forest Management Committees (JFMC). This will provide facilities to the tourists as well employment opportunities to unemployed youths of JFMC. A provision of Rs. 300 lakh is proposed for the year 2012-13 for improvement of infrastructure, basic amenities in these areas and training of JFMC members.

(18) Assisted Natural Regeneration Work in Harvested Timber and Bamboo Coupes

A. Improvement Felling Series Coupes

Harvesting of timber coupes is done as per the working plan prescriptions of the division. The regeneration works in the harvested coupes have to be done as per the prescriptions of working plan and at the same time the area needs to be protected from fire and grazing so to establish the regeneration. These areas should get treatment as per class-I areas. But due to scarcity of funds only part treatment of the prescriptions was possible. It has been decided that all felled coupes of Selection cum Improvement (SCI) working circle will be treated under CAMPA scheme. So to meet the requirements of coupes of Improvement Felling working circle it has been decided to take up this work under 13th Finance Commission grants. For this purpose an amount of Rs. 808 lakh is proposed for the year 2012-13.

B. Regeneration Work in Felled Bamboo Coupes

Bamboo coupes are harvested as per the working plan of the division. In these coupes many of the bamboo clumps which are either congested or hacked and contains less numbers of bamboos, are left un-worked by the labourers because their working is not remunerative. This results in bamboo coupes getting converted into unproductive coupes. So to maintain sustainable supply of bamboos it is silviculturally required that all un-worked bamboo clumps should be worked so to remove the congestion and earth work needs to done to strengthen the clump formation. This activity will result into improvement of bamboo forest and increase in productivity of bamboo coupes in the next felling cycle. For the purpose of Rehabilitation of un-worked bamboo clumps of Bamboo coupes an amount of Rs. 275 lakh is proposed for the year 2012-13.

Total financial requirement for 2012-13 is Rs. 10278 lakhs. The physical and financial targets are given in the annexure-I.

Addl. P.C.C.F. (Dev./Plan)
Chhattisgarh, Raipur

Year 2012-13
Work wise Financial Proposal Under 13th Finance Commssion

(Rs. In lakhs)

S. No.	Description of the work	Unit	2012-13	
			Physical	Financial
1	2	3	4	5
1	Installation of generators at important offices	No.	50	200
2	Community organization and capacity Building/Training	No.	400	70
3	Improving rural infrastructure in Forest village		100 Forest Village	900
4	Implementing poverty alleviation and income generating activities	No.	5 Villages	50
5	Upgradation of Forest Roads			
	a. Maintenance of 650 Km WBM Road	KM	650	2100
	b. Upgradation of 150 km into WBM Road	KM	150	
6	Rehabilitation & Regeneration (including plantation) of Degraded forests and Bamboo Forests in Orange areas (undemarcated PFs)	Ha.	7000	1500
7	Upgradation of Nurseries (Part)	No.	20	500
8	Non convention energy resources, Rain water harvesting		L.S.	125
9	Improvement of Basic Amenities in Forest Colonies		L.S.	250
10	Construction and strengthening of Forest Barriers	No.	50	200
11	Wildlife Habitat Development Outside Protected Area	No.	60 spots	1000
12	Entry point activity in JFM Committees	JFMC no.	150	750
13	Infrastructure Development works Proposed in sale Depot	No.	12	600
14	Training and Development of training infrastructure		L.S.	250
15	Infrastructure Development in New Divisional Head Quarter		L.S.	200
16	Environmental Education to School/College Students		2000 students	200
17	Eco-Tourism Development outside Protected Areas through local JFMC's		10 spots	300
18	Assisted Natural Regeneration Work in Harvested Coupes			
	a. IFS Coupes	Ha.	10000	808
	b. Bamboo Coupes	Ha.	3000	275
	Grand Total :-			**10278**

A.P.C.C.F. (Dev./Plan.)
Chhattisgarh, Raipur

13 वें वित्त आयोग की योजना वर्ष 2011–12 के प्रावधान में आंशिक संशोधन प्रस्ताव की तालिका

क्र.	अनुमोदित कार्य का नाम	प्रावधानित राशि	संशोधन प्रस्ताव में कार्य का नाम	कार्य पर होने वाला व्यय
1	04 जेलों में आर.सी.सी.डबल वाल का निर्माण (जिला जेल दन्तेवाड़ा, कांकेर, जशपुर एवं उप जेल सूरजपुर) (जिला जेल दन्तेवाडा के प्रावधान को छोड़कर अन्य 03 जेलों के कार्य में संशोधन हेतु)	1600.00 लाख	1. केन्द्रीय जेल दुर्ग का विस्तारीकरण कार्य	377.10 लाख
			2. केन्द्रीय जेल जगदलपुर के मुख्य दीवार पर कंसर्टीना वायर फेंसिंग कार्य	15.00 लाख
			3. जिला जेल कांकेर की मुख्य दीवार की ऊँचाई बढ़ाकर कंसर्टीना वायर फेंसिंग कार्य	537.00 लाख
			जेल प्रहरी स्टाफ के लिए प्रशिक्षण केन्द्र एवं आवास व्यवस्था	330.00 लाख
			योग	**1244.00 लाख**